



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-24] रुड़की, शनिवार, दिनांक 11 मार्च, 2023 ई0 (फाल्गुन 20, 1944 शक सम्वत्) [संख्या-10

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

| विषय | पृष्ठ संख्या | वार्षिक चन्दा |
|---|--------------|---------------|
| सम्पूर्ण गजट का मूल्य ... | — | ₹0 |
| भाग 1—विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ... | 287-318 | 3075 |
| भाग 1—क—नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ... | 99-103 | 1500 |
| भाग 2—आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के संस्करण ... | — | 1500 |
| भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ... | — | 975 |
| भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड ... | — | 975 |
| भाग 5—एक्साइज्ड जनरल, उत्तराखण्ड ... | — | 975 |
| भाग 6—बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटीओं की रिपोर्ट ... | — | 975 |
| भाग 7—इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ... | — | 975 |
| भाग 8—सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ... | — | 975 |
| स्टोर्स पर्वेज—स्टोर्स पर्वेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ... | — | 1425 |

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

September 29, 2022

No.1179/XX-5/2022/03(58)2022--Whereas, the Central Government, in exercise of powers conferred by section 3(1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), has declared the Popular Front of India(PFI) and its associates or affiliates or fronts, including Rehab India Foundation (RIF), Campus Front of India (CFI), All India Imams Council (AIIC), National Confederation of Human Rights Organization (NCHRO), National Women's Front, Junior Front, Empower India Foundation and Rehab Foundation, Kerala as unlawful association vide notification number S.O.No. 4559(E) dated 27th September, 2022;

And whereas, in exercise of the powers conferred by section 42 of the said Act, the Central Government has directed vide Notification No. S.O. 4560(E) dated 28th September, 2022 that all the States and Union Territory Administrations shall exercise the power exercisable by the Central Government under Section 7 and Section 8 of the said Act;

And whereas, vide order No. 14017/4/2022-NI-MFO dated 28th September, 2022 (Copy enclosed) it has been conveyed that the State Government and Union Territory Administrations may, by order in writing, direct that any power which has been directed to be exercised by it, shall, in such circumstances and under such conditions, as may be specified in the direction, be exercised by the Commissioners of Police, the District Magistrates or the Deputy Commissioners of Districts under the State Governments and Union Territory Administrations;

Now, therefore, in exercise of the aforesaid delegated powers, the State Government hereby directs that all the District Magistrates, the Senior Superintendents of Police/ Superintendents of Police shall exercise the powers accordingly.

BY ORDER AND ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF
UTTARAKHAND.

By Order,

DR. S.S. SANDHU,

Chief Secretary to the
Govt. of Uttarakhand.

वित्त अनुभाग-8

अधिसूचना

02 दिसम्बर, 2022 ई०

संख्या 80481/2022/07(100)/XXVII(8)/2008—मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के संस्तुति पत्र सं०-5041/XIII-f-7/Admin-A/2004, दिनांक 16.11.2022 के क्रम में उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूल एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा-84 की उपधारा (2)(क) एवं उपधारा (4)(क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री सी०पी० विजलवाण, मा० अध्यक्ष, राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण, उत्तराखण्ड देहरादून को उनके वर्तमान कर्तव्यों के अतिरिक्त अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पद पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

आनन्द बर्द्धन,

अपर मुख्य सचिव।

गृह अनुभाग-8

अधिसूचना

08 फरवरी, 2023 ई०

संख्या 30/XX-6/2023-11(08)2016—राज्यपाल, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्यांक 2) की धारा 2 के खण्ड (घ) एवं इस सम्बन्ध में प्रदत्त समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला देहरादून के अन्तर्गत देख-रेख पुलिस चौकी सहिया को वर्तमान थाना चकराता के अधिकारिता क्षेत्र से हटाकर थाना कालसी तहसील कालसी के अधिकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2— उक्तानुसार अधिसूचना संख्या 2225 (22)/XX-1/11/154/ई.ग./2011 दिनांक 12 दिसम्बर, 2011 को उक्त सीमा तक संशोधित पढ़ा/समझा जाए।

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the "Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.30/XX-6/2023-11(08)2016 Dehradun dated: February 06, 2023 for general information.

NOTIFICATION

February 06, 2023

No.30/XX-6/2023-11(08)2016--In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of the Act of 1974) & all the enabling powers conferred in this behalf, the Governor is pleased to include the outpost Sahia in the jurisdiction of Police Station Kalsi and shall be excluded from the jurisdiction of Police Station Chakrata in District Dehradun.

2. Notification no. 2225(22)/XX-1/11/154/E.Ga./2011, dated 12.12.2011 deemed to be amended to the said limit.

अधिसूचना

06 फरवरी, 2023 ई0

संख्या 42/XX-6/2023-11(08)2016—राज्यपाल, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्यांक 2) की धारा 2 के खण्ड (घ) एवं इस सम्बन्ध में प्रदत्त समस्त सभ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला चम्पावत के अन्तर्गत पड़ने वाले ग्राम 1—सल्ली, 2—सतकुला एवं 3—कुक्डोनी को वर्तमान थाना तामली के अधिकारिता क्षेत्र से हटाकर कोतवाली चम्पावत के अधिकारिता क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2— उक्तानुसार अधिसूचना संख्या 564/XX-1/11/पु0ई0नि0/2005 दिनांक 11 जुलाई, 2007 को उक्त सीमा तक संशोधित पढ़ा/समझा जाए।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,

अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the "Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.42/XX-6/2023-11(08)2016 Dehradun, Dated: February 06, 2023 for general information.

NOTIFICATION

February 06, 2023

No.42/XX-6/2023-11(08)2016--In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of the Act of 1974) & all the enabling powers conferred in this behalf, the Governor is pleased to include the villages 1-Salli 2-Satkula & 3-Kukdoni in the jurisdiction of kotwali Champawat and shall be excluded from the jurisdiction of Police Station Tamli in district Champawat.

2. Notification no. 564/XX-1/11/154/Pu.E.Ni./2005, dated 11.07.2007 deemed to be amended to the said limit.

By Order,

RADHA RATURI,

Additional Chief Secretary,

कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग-2**अधिसूचना**

01 फरवरी, 2023 ई०

संख्या: 121/XIII-2/2023-61(कृषि)/2001—उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड) की धारा 10(1)(K) एवं विश्वविद्यालय परिनियमों के अध्याय XXX में निहित प्राविधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचक मण्डल, पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा निर्वाचित डा० विशाल राणा, पशु चिकित्साधिकारी (परिचयांक 16263) को गोविन्द नल्लम पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर (कछमसिंह नगर) की प्रबन्ध परिषद में पंजीकृत स्नातक सदस्य के रूप में नामित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. श्री राज्यपाल, उक्त अधिनियम की धारा 10(1)(K) एवं विश्वविद्यालय परिनियमों के अध्याय XXX में निहित प्राविधानों के अधीन उक्तवत नामित सदस्य का कार्यकाल इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष भी नियत करते हैं।

आज्ञा से,

बी०वी०आर०सी० पुरुषोत्तम,
सचिव।**राजस्व अनुभाग-3****अधिसूचना**

02 फरवरी, 2023 ई०

संख्या: 71/XVIII(3)/2023-03(6)/2016—राज्यपाल, उत्तर प्रदेश नू-राजस्व अधिनियम, 1901 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 3 सन् 1901) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करते हैं कि नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित ग्राम, जिसे अधिसूचना संख्या-70/1-14-2000-48(2)-94-81, दिनांक 10 मार्च, 2000 द्वारा सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाओं के अधीन रखा गया था, में सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाएँ इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से बन्द हो जावेंगी।

अनुसूची

| जिला | तहसील | परगना | ग्राम का नाम |
|-------------|----------|------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| कछमसिंह नगर | सितारगंज | मैनाझुण्डी | बिज्जी |

आज्ञा से,

सचिन कुर्वे,

सचिव, राजस्व।

In pursuance of the provision of clause (3) of the article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 71/XVIII(3)/2023-03(6)/2016 Dated: February 02, 2023 for general information.

NOTIFICATION

February 02, 2023

No. 71/XVIII(3)/2023-03(6)/2016--In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901 (U.P. Act No. 03 of 1901) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor declare that the Survey and Record Operation in the village mentioned in the Schedule

below which were placed under Survey and Record Operation Vide Govt. Notification No. 70/1-14-2000-49(2)-94-81, dated 10 March, 2000 shall be closed with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette.

Schedule

| District | Tehsil | Pargana | Name of Village |
|-------------------|-----------|-------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Udham Singh Nagar | Sitarganj | Mainajhundi | Bijti |

By Order,
SACHIN KURVE,
Secretary, Revenue.

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, अनुभाग-2

अधिसूचना

09 फरवरी, 2023 ई०

संख्या e-file./Comp.No.-29889/2022-राज्यपाल, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री निशान्त त्यागी, राजकीय विश्लेषक (औषधि), खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला, रुद्रपुर (उधमसिंह नगर) को सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न औषधियों या औषधियों के वर्गों अथवा सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री या सौन्दर्य प्रसाधन सामग्रियों के वर्गों के परीक्षण एवं विश्लेषण हेतु सरकारी विश्लेषक नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
डॉ० आर० राजेश कुमार,
राधिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No./ 97768/2023 Dated: February 09, 2023 for general information.

NOTIFICATION

February 09, 2023

e-file./Comp.No.-29889/2022-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940, the Governor is pleased to approve to appoint Shri Nishant Tyagi, Government Analyst (Drugs), Food and Drug Laboratory, Rudrapur (Udham Singh Nagar) as Government Analysts for testing and analysis of various drugs or classes of drugs or classes of cosmetics or cosmetics in the whole State of Uttarakhand.

By Order,
DR. R. RAJESH KUMAR,
Secretary.

वन अनुभाग-2

अधिसूचना

प्रकीर्ण

09 फरवरी, 2023 ई०

संख्या 289/X-2-2023-19(09)2002-उत्तराखण्ड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 18वीं बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में राज्य में शिवालिक एलिफैंट रिजर्व को निरस्त किये जाने सम्बन्धी उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-78/X-2-2021-19(09)2002 दिनांक 08.01.2021 एवं संख्या-278/X-2-2021-153/2021, दिनांक 28.01.2021 को निरस्त करते हुए उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-1777/1(2)/व.ग्रा.वि./202-19(9)/2002, दिनांक 28.10.2002 द्वारा घोषित शिवालिक एलिफैंट रिजर्व को पुनर्स्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

विजय कुमार यादव,
सचिव।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग

कार्यालय ज्ञाप

21 फरवरी, 2023 ई०

संख्या 370/VII-3-23/34-एम०एस०एम०ई०/2016-सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या:-999/VII-2/34-एम०एस०एम०ई०/2016 दिनांक 26 मई, 2016 के प्रस्तर-1 'आवंटन हेतु उपलब्ध शेड तथा भूखण्डों की जानकारी दिया जाना' शीर्ष के अंतर्गत पैरा-2 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या:-1035/VII-3-22/34-एम०एस०एम०ई०/2016 दिनांक 12 सितम्बर, 2022 के प्रस्तर-6(1) में प्रतिस्थापित वर्तमान प्राविधानों/व्यवस्था के स्थान पर श्री राज्यपाल महोदय स्तम्भ-2 में उल्लिखित निम्नलिखित प्राविधान/व्यवस्था प्रतिस्थापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

| स्तम्भ-1 वर्तमान व्यवस्था | स्तम्भ-2 प्रतिस्थापित/संशोधित व्यवस्था |
|---|--|
| प्रस्तर-1 ऑनलाईन आवेदन करने के बाद आवेदक मैन्युअल भी वेबसाइट पर अपलोड आवेदन पत्र की प्रति निर्धारित शुल्क तथा अन्य अपेक्षित अभिलेख संबंधित जिला उद्योग केन्द्र में निर्धारित अवधि के अन्दर जमा कर देंगे अन्यथा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। | प्रस्तर-1 रिक्त मूखण्डों/शेडों के आवंटन हेतु विज्ञापित जारी होने के पश्चात् आवेदक द्वारा विज्ञापित में दी गयी समयावधि के भीतर निर्धारित प्रारूप पर वांछित अभिलेख/दस्तावेजों सहित विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाईन आवेदन करना आवश्यक होगा, अन्यथा की स्थिति में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। |

| | |
|--|--|
| <p>प्रस्तर-8(1) विभागीय औद्योगिक आस्थानों में भूखण्ड का आवंटन विनिर्माणक उद्योगों के अतिरिक्त सेवा क्षेत्र की चिन्हित निम्न गतिविधियों के संचालन/स्थापना के लिए किया जायेगा:-</p> | <p>प्रस्तर-8(1) विभागीय औद्योगिक आस्थानों में भूखण्ड का आवंटन विनिर्माणक उद्योगों के अतिरिक्त सेवा क्षेत्र की निम्नांकित चिन्हित गतिविधियों (Annexure-1&-2) के संचालन/स्थापना के लिए किया जावेगा:-</p> |
| <p><u>सेवा क्षेत्र की चिन्हित गतिविधियां:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा संस्थान। • ऑटोमोबाइल मरम्मत एवं सर्विसेज। • लॉण्ड्री। • बैंकिंग सेवा (अधिकतम दो बैंकों की स्थापना हेतु)। • जैव प्रौद्योगिकी। • सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएँ। | <p><u>सेवा क्षेत्र की चिन्हित गतिविधियां:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • जैव प्रौद्योगिकी (Annexure-1)। • सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएँ (Annexure-2)। |

आज्ञा से,

डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग

अधिसूचना

22 फरवरी, 2023 ई0

संख्या 372/VII-3-23/166-उद्योग/2011टी0सी0-एतद्वारा राज्य में औद्योगिकीकरण के माध्यम से रोजगार के तहत अवसरों के सृजन तथा बड़े निवेश के लिये उद्यमों को स्थापित करने के लिये आवश्यक समयबद्ध अनुज्ञापन, अनुज्ञार्थ व स्वीकृतियां प्रदान करने के लिये उत्तराखण्ड एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम, 2012 प्रख्यापित किया गया है। इसी अधिनियम की धारा 14 में विहित प्राविधान के दृष्टिगत व निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिये "प्रवर्ग विशेष के उद्यमों को अनुकूलित पैकेज/रियायत स्वीकृत किये जाने हेतु प्रक्रिया एवं दिशानिर्देशों (संलग्नक) के प्रख्यापन" की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अधिसूचना संख्या: 372/VII-3-23/168-उद्योग/2011 टी०सी०, दिनांक 22 फरवरी, 2023 का संलग्नक

अनुलग्नक

प्रवर्ग विशेष के उद्यमों को अनुकूलित पैकेज/रियायत स्वीकृत किये जाने हेतु उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम, 2012 की धारा-14 के अन्तर्गत अनुकूलित पैकेज हेतु दिशानिर्देश विनिर्माणक और सेवा क्षेत्र में निवेश संवर्द्धन के लिए उद्योगों को अनुकूलित पैकेज की स्वीकृति हेतु दिशानिर्देश।

1. संदर्भ

- 1.1 उत्तराखण्ड निवेश शिखर सम्मेलन 2018 की सफलता के साथ, बहुत से व्यवसायियों ने उत्तराखण्ड में निवेश कर राज्य के आर्थिक विकास में अपना सहयोग दिया है। विभिन्न क्षेत्रों में कई छोटी और बड़ी परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को सरकार की नीतियों, अर्थात् उत्तराखण्ड एमएसएमई नीति और मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति के साथ-साथ क्षेत्र-विशिष्ट नीतियों के माध्यम से वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए गये हैं। इनमें से कई परियोजनाओं की स्थापना का कार्य पूर्ण कर उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया है। अभी भी कई बड़ी परियोजनाएँ ग्राउण्डिंग के लिए पाइपलाइन में हैं।
- 1.2 अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति-2021 के तहत प्रदान किए गए निवेश के लिए प्रोत्साहन का अनुपात निवेश की मात्रा बढ़ने पर कम हो जाता है। मामले के अध्ययन करने पर (अनुबंध-7) यह स्पष्ट हुआ है कि रु. 100 करोड़ और रु. 300 करोड़ के निवेश की परियोजनाओं में पूंजी निवेश बढ़ने पर अनुदान या प्रोत्साहन का प्रभाव प्रतिशत के संदर्भ में कम हो जाता है, क्योंकि प्रोत्साहन सहायता के अनुपात में परियोजना की लागत उच्च निवेश की ओर बढ़ती रहती है।
- 1.3 यह भी स्पष्ट हुआ है कि अल्ट्रा-मेगा परियोजनाएं, औद्योगिक विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती हैं और सहायक तथा अनुप्रवाह उद्योगों को आकर्षित करता है। बड़ी परियोजनाओं के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्य मामले-दर-मामला आधार पर अनुकूलित प्रोत्साहन पैकेज प्रदान कर रहे हैं। उत्तराखण्ड के संदर्भ में, इन परियोजनाओं को अल्ट्रा मेगा या विशेष श्रेणी की परियोजनाओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ऐसे उद्योगों को राज्य के भीतर औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अधिमान्य या अनुकूलित प्रोत्साहन पैकेज दिए जा सकते हैं।
- 1.4 उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम, 2012 की धारा-14 के तहत अनुकूलित पैकेज प्रदान करने का प्रावधान है, लेकिन दिशानिर्देशों के अधीन और कार्यान्वयन के लिए एक अधिसूचित प्रक्रिया न होने के कारण इसका उपयोग नहीं किया गया है। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि बृहत परियोजनाओं के लिए अनुकूलित प्रोत्साहन के प्रावधान को क्रियान्वित करने हेतु दिशानिर्देश तैयार किए जाएं। जैसा कि मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति में परिभाषित किया गया है, ये दिशानिर्देश केवल लार्ज, मेगा, अल्ट्रा मेगा तथा सुपर अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं पर लागू होते हैं। रु. 200 करोड़ अथवा इससे अधिक अचल पूंजी निवेश की परियोजनाओं को अनुकूलित पैकेज प्रदान करने तथा इस प्रावधान के प्रभावी और सुचारु कार्यान्वयन के लिए यह दिशानिर्देश प्रख्यापित किए जा रहे हैं।

2. परिभाषा

- 2.1 दिशानिर्देश: उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम, 2012 की धारा-14 के तहत अनुकूलित पैकेज के लिए दिशानिर्देश।

- 2.2 आवेदक इन दिशानिर्देशों के प्रयोजन के लिए, आवेदक पात्रता मानदंड के अनुसार भारत में पंजीकृत एक इकाई होनी चाहिए, जो राज्य में माल/वस्तुओं के निर्माण या राज्य से सेवाएं प्रदान करने का प्रस्ताव करता है और इन दिशानिर्देशों के तहत अनुकूलित प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए आवेदन कर रहा है। आवेदक को राज्य में किसी भी ग्रीनफील्ड या ब्राउन फील्ड परियोजना में विस्तार/विविधीकरण में एक प्रारंभिक निश्चित निवेश करना होगा।
- 2.3 आवेदन पत्र: एक आवेदक द्वारा परियोजना समीक्षा समिति (पीआरसी) को इन दिशानिर्देशों के अधीन निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप पर सूचनाओं एवं अन्य वांछित अभिलेखों तथा आवेदन शुल्क के साथ प्रस्तुत किया गया आवेदन।
- 2.4 आवेदन यावती तिथि: जिस तारीख को इस संबंध में प्रारंभिक जांच करने के बाद परियोजना समीक्षा समिति द्वारा एक आवेदन को स्वीकार किया गया है।
- 2.5 आवेदन स्वीकृति तिथि: वह तिथि, जिस तिथि को प्राधिकृत समिति (ईसी) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत आश्वासन पत्र "निश्चय पत्र" जारी किया गया है।
- 2.6 आधार वर्ष: जिस वर्ष में आवेदन जमा किया जाता है, उसे आधार वर्ष माना जाएगा।
- 2.7 ब्राउनफील्ड परियोजना: कोई भी पात्र परियोजना, सीमा से अधिक, या तो चालू या गैर-संचालन, या तो वर्तमान मालिक या नए मालिक द्वारा जहां नया निवेश किया जा रहा है। तथापि, इन दिशानिर्देशों के प्रयोजन के लिए मौजूदा सुविधा के विस्तार के लिए अलग रिकॉर्ड बनाए रखा जाएगा।
- 2.8 वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि: जिस तारीख को आवेदक दिशानिर्देशों के तहत निर्मित योग्य उत्पादों की बिक्री के लिए पहला जीएसटी धालान जारी करता है।
- 2.9 रोजगार का अर्थ है, उत्पादन प्रक्रिया या उत्पादन सुविधा के लिए, जब कच्चा माल संबंधित गतिविधियों के संचालन हेतु उपयोग में लाया जाता है और अन्तिम उत्पाद के निर्माण तक संलग्न प्रक्रिया से सृजित प्रत्यक्ष रोजगार। सेवाओं के मामले में, सेवायोजन की संख्या की गणना आवेदक द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियोजित लोगों में से की जायेगी। सहयोग अथवा तीसरे पक्ष द्वारा नियोजित लोगों को इसमें सम्मिलित नहीं किया जायेगा। इस तरह के रोजगार में इकाई में ऑन-रोल, संविदात्मक और अपरेंटिस कार्यबल भी शामिल होंगे।
- 2.10 परियोजना समीक्षा समिति (पीआरसी): आवेदनों की समीक्षा एवं जांच सचिव, उद्योग की अध्यक्षता में गठित एक सदस्यीय समिति द्वारा की जायेगी। महानिदेशक/आयुक्त उद्योग तथा निदेशक उद्योग संभावित आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण करने, अतिरिक्त जानकारी एकत्र करने में सहायता, परियोजना के बारे में वित्तीय जानकारी को समझने और अवगत कराने आदि के लिए सचिव, उद्योग को सहायता प्रदान करेंगे। परियोजना समीक्षा समिति आवेदक द्वारा प्रस्तुत परियोजना विवरण का मूल्यांकन करेगा और इसमें आवश्यक अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के साथ-साथ स्थलीय निरीक्षण भी किया जा सकता है। परियोजना समीक्षा समिति अपनी संस्तुति प्राधिकृत समिति को प्रस्तुत करेगी। सचिव, उद्योग आवश्यकता पड़ने पर केंद्र/राज्य सरकारों या अन्यथा जैसे कानूनी, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, अन्य क्षेत्रों आदि से अन्य विशेषज्ञों को इस प्रक्रिया में शामिल अथवा उनका परामर्श प्राप्त कर सकते हैं।
- 2.11 प्राधिकृत समिति (ईसी): प्राधिकृत समिति का स्वरूप निम्नानुसार होगा:
- | | | |
|----|----------------------------------|--------------------------|
| 1. | मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन | अध्यक्ष, प्राधिकृत समिति |
| 2. | सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन | सदस्य |
| 3. | सचिव, उद्योग, उत्तराखण्ड शासन या | सदस्य सचिव |

परियोजना समीक्षा समिति का अध्यक्ष

2.12 उच्च प्राधिकृत समिति (एचईसी): उच्च प्राधिकृत समिति का स्वरूप निम्नानुसार होगा:

- | | | |
|----|--|---------|
| 1. | भा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड | अध्यक्ष |
| 2. | भा० मंत्री, औद्योगिक विकास, उत्तराखण्ड | सदस्य |

2.13 वित्तीय वर्ष: वित्तीय वर्ष का तात्पर्य 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष से है।

2.14 अप्रत्याशित घटना: असाधारण घटनाएँ या परिस्थितियाँ जो मानव नियंत्रण से परे हैं जैसे कि ईश्वर के कार्य के रूप में वर्णित घटनाएँ (जैसे प्राकृतिक आपदा) या युद्ध, हड़ताल, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल, दंगे, अपराध जैसी घटनाएँ (लेकिन इसमें लापरवाही या गलत काम, अनुमानित मौसमी बारिश और विशेष रूप से बाहर रखी गई कोई अन्य घटना शामिल नहीं हैं)।

2.15 ग्रीनफील्ड परियोजना: एक पात्र परियोजना जिसमें आवेदक द्वारा इन दिशानिर्देशों के तहत एक नई उत्पादन/सेवा सुविधा या विस्तार के उद्देश्य के लिए प्रारम्भिक निवेश की समान निवेश राशि में न्यूनतम प्रारम्भिक निवेश करने का प्रस्ताव है। इन दिशानिर्देशों के प्रयोजन के लिए अलग-अलग रिकॉर्ड बनाए जाने हैं।

2.16 प्रोत्साहन का अर्थ इन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के आधार पर प्रत्येक चयनित आवेदक को प्रदान किया जाने वाला वित्तीय प्रोत्साहन/लाभ से है।

2.17 पात्र निवेश: नए संयंत्र, यथा भवन, मशीनरी, उपकरण और उसी की सबद्ध उपयोगिताओं (पुर्जो एक्सेसरीज, कंपोनेंट्स और उसके पुर्जो सहित) पर किया गया व्यय, जो किसी भी निर्मित माल या सेवाओं के डिजाइन निर्माण, संयोजन, परीक्षण, पैकेजिंग या प्रसस्करण में उपयोग किया जाता है एसोसिएटेड यूटिलिटीज में सर्वर, सॉफ्टवेयर और ईआरपी समाधान सहित विनिर्माण से संबंधित आईटी और आईटीईएस अवसंरचना भी शामिल होगी। उक्त परिभाषित संयंत्र, मशीन और उपकरण की लागत में इनके परिवहन, अधिष्ठापन, बीमा शुल्क को भी सम्मिलित किया जायेगा।

2.18 अपात्र निवेश: इन दिशानिर्देशों के तहत परियोजना/इकाई के लिए आवश्यक भूमि, भूमि विकास या कार्यशील पूँजी पर किए गए व्यय को प्रारम्भिक निवेश सीमा के हिस्से के रूप में नहीं माना जाएगा।

2.19 सक्षम प्राधिकारी: परियोजना समीक्षा समिति या प्राधिकृत समिति द्वारा नियुक्त अधिकृत प्राधिकारी/सक्षम प्राधिकारी, जो आवेदनों की प्राप्ति और मूल्यांकन, पात्रता के स्थापन और उचित समझे जाने वाले किसी भी तरीके/दस्तावेज के माध्यम से सवितरण दावों की जांच के लिए अपनी ओर से कार्य करने तथा इन दिशानिर्देशों के अनुसार उपर्युक्त प्रबंधन के लिए उत्तरदायी हो।

2.20 ग्रेसहोल्ड निवेश: इन दिशानिर्देशों के पात्रता मानदंड के तहत निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अन्तर्गत पात्रता के लिए निर्धारित न्यूनतम निवेश।

2.21 ग्रेसहोल्ड रोजगार: इन दिशानिर्देशों के पात्रता मानदंड के तहत निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अन्तर्गत पात्रता के लिए सृजित किए जाने वाले रोजगार की न्यूनतम संख्या।

3. वैधता:

3.1 यह दिशानिर्देश अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होंगे और अगले पांच वर्षों तक प्रभावी रहेंगे।

3.2 इन दिशानिर्देशों के प्रावधानों में किसी भी प्रकार की छूट प्रदान करने का अधिकार सरकार में निहित होगा।

3.3 मा0 मुख्यमंत्री, प्राधिकृत समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर, इन दिशानिर्देशों में, यदि आवश्यक हो, संशोधन कर सकते हैं।

4. पात्रता मानदंड और आवेदक का चयन

4.1 आवेदन के लिए पात्रता

4.1.1 फर्म को 'कंपनी अधिनियम, 2013' (संशोधनों सहित) के तहत कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए। भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप भी आवेदन करने के पात्र होंगे।

4.1.2 विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में निवेश, दोनों लाभ के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

4.1.3 आवेदक को दिवालिया या विलफुल डिफॉल्टर या डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया हो या किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा धोखाधड़ी के लिए उसके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी हो।

4.1.4 न्यूनतम थ्रेसहोल्ड सीमा:

4.1.4.1 निवेश: 200 करोड़ रुपये या उससे अधिक के 'निवेश' वाली परियोजनाएं इन दिशानिर्देशों के तहत लाभ के लिए पात्र होंगी, या

4.1.4.2 रोजगार प्रचालन के पहले वर्ष से आवेदक इकाई 500 व्यक्तियों को वर्ष में प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करने में सक्षम हो।

4.1.5 इन दिशानिर्देशों के तहत आवेदक को अनुमोदित वित्तीय प्रोत्साहनों के वितरण की पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से, आवेदक खण्ड 4.1.4 के तहत उल्लिखित न्यूनतम सीमा मानदंड को पूरा करने और इसके प्रारंभ होने के बाद प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र होगा:

4.1.5.1 विनिर्माण क्षेत्र की इकाइयों के लिए स्वनिर्मित उत्पाद के उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात्।

4.1.5.2 सेवा क्षेत्र की इकाइयों के लिए उत्तराखण्ड एसजीएसटी आधारित चालान पर व्यवसायिक गतिविधि के प्रचालन का प्रथम बिल जारी करने के दिनांक के पश्चात्।

4.1.6 इन दिशानिर्देशों के तहत पात्रता किसी अन्य नीति के तहत पात्रता को प्रभावित नहीं करेगी या इसके विपरीत नहीं होगी।

4.1.7 अनुकूलित पैकेज के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने वाले आवेदक उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य नीतियों के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे।

4.1.8 पात्र आवेदक, खण्ड-2.16 के अनुसार पात्र निवेश के 100 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत कुल अनुमन्य प्रोत्साहन सहायता के अधीन, भारत सरकार की किसी अन्य योजना में प्रदत्त प्रोत्साहन सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं।

4.2 चयन:

4.2.1 परियोजना समीक्षा समिति आवेदन के आधार पर मूल्यांकन करेगा जिसके आधार पर वह परियोजना की सिफारिश प्राधिकृत समिति को अनुमोदन के लिए भेजेगा। मूल्यांकन के

लिए चेकलिस्ट अनुबंध 8 में दी गई है।

- 4.2.2 परियोजना समीक्षा समिति को एक आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार है, भले ही आवेदक न्यूनतम निवेश मानदंडों को पूरा करता हो। परियोजना समीक्षा समिति को आवेदन की अस्वीकृति के लिए प्रासंगिक कारण बताना होगा। अस्वीकृति का कारण आवेदक के साथ साझा नहीं किया जाएगा, लेकिन प्राधिकृत समिति के समक्ष समीक्षा के उद्देश्य से यह आवेदन/दस्तावेज प्रस्तुत किया जायेगा।

5. निवेश राशि की पात्रता के लिए नियम एवं शर्तें:

5.1 सामान्य नियम और शर्तें:

- 5.1.1 चूंकि ऐसे अनुकूलित पैकेजों को प्रदान करने से पहले अन्य राज्य सरकारों द्वारा गैर-प्रकटीकरण समझौता किया जाता है और परियोजनाओं को दी जा रही प्रोत्साहन राशि के बारे में जानकारी सरकार और इकाई के बीच में ही रहती है। यदि इकाई एनडीए का उल्लंघन करती है, तो इकाई प्रदान की जा रही प्रोत्साहन राशि ब्याज सहित वापस करने के लिए उत्तरदायी होगी।
- 5.1.2 इन दिशानिर्देशों में परिभाषित निवेश, दिशानिर्देशों के तहत पात्रता निर्धारित करने के लिए विचार किया जाएगा बशर्ते कि ऐसा निवेश इन दिशानिर्देशों के जारी होने के बाद किया गया हो।
- 5.1.3 उपभोज्य सामग्रियों और विनिर्माण के लिए प्रयुक्त कच्चे माल पर व्यय को निवेश के रूप में नहीं माना जाएगा।
- 5.1.4 दिशानिर्देशों के तहत खरीद चालान की तारीख को निवेश की तारीख माना जाएगा।
- 5.1.5 पात्र निवेश के किसी भी हिस्से के लिए बिलिंग वृत्त उत्तराखण्ड राज्य में अवस्थित किसी स्थान का होना चाहिए।
- 5.1.6 आवेदक इकाई एक समझौते पर हस्ताक्षर करके एक परिचालन लॉक-इन अवधि में प्रवेश करेगी, जो कि उत्पादन शुरू होने की तारीख से न्यूनतम 15 वर्ष की होगी:
- 5.1.6.1 विनिर्माण क्षेत्र की इकाइयों के लिए परियोजना का उत्पादन।
- 5.1.6.2 सेवा क्षेत्र की इकाइयों के लिए उत्तराखण्ड एसजीएसटी आधारित चालान पर पहली बिक्री को मान्यता।

5.2 संयंत्र, मशीनरी और उपकरण के लिए नियम एवं शर्तें

- 5.2.1 इन दिशानिर्देशों के खंड 2.15.1 में परिभाषित नए संयंत्र मशीनरी और उपकरण पर किए गए व्यय को इन दिशानिर्देशों के तहत पात्रता निर्धारित करने के लिए निवेश के रूप में माना जाएगा।
- 5.2.2 आवेदक के नाम पर नया संयंत्र, मशीनरी और उपकरण खरीद/पट्टे पर लिया जाना चाहिए। जिन मामलों में इन्हें पट्टे पर दिया जा रहा है, पट्टा लेखा मानक 19 पट्टे या भारतीय लेखा मानक - 118 पट्टे के अर्थ के भीतर एक वित्तीय पट्टे की प्रकृति में होना चाहिए, जैसा कि आवेदक पर लागू हो सकता है, जैसा कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या समय-समय पर किसी अन्य उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित किया गया है।
- 5.2.3 लागू करों और शुल्कों के भुगतान के बाद कानूनी रूप से वैध दस्तावेजों के माध्यम से संयंत्र, मशीनरी और उपकरण की खरीद या पट्टे पर ली जानी चाहिए।

6. आवेदन की प्रक्रिया

- 6.1 आवेदन के साथ जमा की गई सूचना/आकड़े के सत्यापन के लिए आवेदक को अपने निर्माण स्थल/कार्यालयों के अनुबंध-1 की सहमति वाले ऑडिट के प्रारूप में एक अडरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी।
- 6.2 निर्धारित प्रारूप में एक आवेदन प्राप्त होने पर, परियोजना समीक्षा समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या आवेदन प्रथम दृष्टया इन दिशानिर्देशों में निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा करता है। पूर्वोक्त प्रथम दृष्टया परीक्षा में मूल आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 15 कार्य दिवसों के भीतर या यदि मूल आवेदन अपूर्ण होने पर वापस कर दिया गया हो, तो संशोधित आवेदन जमा करने की तारीख से 15 कार्य दिवसों के भीतर पूरी की जाएगी।
- 6.3 यदि उपर्युक्त परीक्षा में कोई आवेदन अपूर्ण पाया जाता है, तो परियोजना समीक्षा समिति आवेदन प्राप्त होने के 15 कार्य दिवसों के भीतर आवेदक को तदनुसार सूचित करेगी।
- 6.4 एक पात्र आवेदन के लिए, परियोजना समीक्षा समिति एक गैर-प्रकटीकरण समझौते के साथ आवेदन प्राप्त होने के 15 कार्य दिवसों के भीतर आवेदन की प्राप्ति की पावती जारी करेगी, जिस पर दोनों पक्षों (आवेदक और परियोजना समीक्षा समिति) द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की आवश्यकता है।
- 6.5 इस पावती को इन दिशानिर्देशों के तहत अनुमोदन या आश्वासन के बाद के रूप में नहीं माना जाएगा, यदि जांच करने पर यह पाया जाता है कि एक मूल या संशोधित आवेदन प्रथम दृष्टया निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो परियोजना समीक्षा समिति आवेदक को आवेदन प्राप्त होने के 15 कार्य दिवसों के भीतर तदनुसार सूचित करेगी।
7. परियोजना समीक्षा समिति (पीआरसी)
 - 7.1 इन दिशानिर्देशों को एक परियोजना समीक्षा समिति (पीआरसी) के माध्यम से लागू किया जाएगा जो सचिवीय, प्रबंधकीय और कार्यान्वयन सहायता प्रदान करने और समय-समय पर प्राधिकृत समिति द्वारा सौंपे गए अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होगी।
 - 7.2 परियोजना समीक्षा समिति निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगी:
 - 7.2.1 आवेदनों की प्राप्ति, आवेदनों की जांच और प्रसंस्करण और पावती जारी करना
 - 7.2.2 इन दिशानिर्देशों के तहत प्राप्त और संशोधित आवेदनों की स्थिति के सम्बन्ध में एक पक्ष के भीतर प्राधिकृत समिति को सूचना/विवरण प्रस्तुत करना।
 - 7.2.3 इन दिशानिर्देशों के तहत आवेदनों के अनुमोदन के लिए प्राधिकृत समिति को उपयुक्त संस्तुति करना।
 - 7.2.4 प्रोत्साहन के सवितरण के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए श्रेसहोल्ड का सत्यापन।
 - 7.2.5 प्रोत्साहन के सवितरण के दावों की जांच करना और प्राधिकृत समिति को उचित संस्तुति करना।
 - 7.2.6 निर्धारित दस्तावेजों के साथ सवितरण दावों के समाधान का सत्यापन।
 - 7.2.7 अनुबंध-3 और अन्य जानकारी/दस्तावेजों के अनुसार तिमाही समीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से इन दिशानिर्देशों की प्रगति और प्रदर्शन के संबंध में आकड़ों का सकलन,
 - 7.3 परियोजना समीक्षा समिति आवश्यक समझे जाने पर आवेदक से अतिरिक्त जानकारी विवरण और दस्तावेजों को माग सकता है।
 - 7.4 परियोजना समीक्षा समिति को स्थलीय निरीक्षण के माध्यम से एक आवेदक की विनिर्माण इकाइयों और कार्यालयों का भौतिक निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

- 7.5 परियोजना समीक्षा समिति को इन दिशानिर्देशों के तहत निवेशकों द्वारा प्राप्त लाभों की समीक्षा, निगरानी, प्रबंधन और कार्यान्वयन और प्रशासनिक कार्य करने के लिए विषय वस्तु, परियोजना प्रबंधन में विशेषज्ञों की एक टीम बनाने का अधिकार होगा।
- 7.6 राज्य में मौजूदा नीतियों और भूमि आवंटन प्रक्रिया के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए आवेदक को समझाने का प्रयास किया जाएगा यदि परियोजना इन दिशानिर्देशों के पात्रता मानदंडों में योग्य है, तो परियोजना प्रस्तावक को एक आवेदन करने के लिए निर्देशित किया जाएगा।
- 7.7 इन दिशानिर्देशों के तहत, दिशानिर्देशों के खंड 5 के अनुसार पात्र निवेश राशि का 100 प्रतिशत तक प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा, जिसकी अधिकतम मात्रा/सीमा उत्पादन प्रारम्भ करने की तारीख से 10 वर्षों की अवधि में विभिन्न राज्य करों, स्टाम्प ड्यूटी और अन्य लेवी के माध्यम से राज्य को अर्जित अनुमानित राजस्व (पूँजी निवेश या परियोजना के ग्राउंडिंग के दौरान भुगतान किए गए करों और लेवी सहित) से अधिक नहीं होगी।
- 7.8 यह सुनिश्चित करने के लिए कि निवेशक द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को लागू किया गया है, प्रतिपूर्ति के माध्यम से प्रोत्साहन प्रदान करना प्राथमिकता होगी। हालाँकि, जैसा कि मामले में अपेक्षित हो, निवेशित पूँजीगत व्यय पर प्रोत्साहन भी प्रदान किया जा सकता है।

8. प्राधिकृत समिति (ईसी)

- 8.1 प्राधिकृत समिति आवेदनों और संवितरण दावों पर समय पर विचार सुनिश्चित करने और इन दिशानिर्देशों की आवधिक समीक्षा करने के लिए जितनी बार आवश्यक हो, बैठक करेगा।
- 8.2 प्राधिकृत समिति इन दिशानिर्देशों के तहत अनुमोदन के लिए परियोजना समीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित आवेदनों पर विचार करेगा। प्राधिकृत समिति ऐसी अतिरिक्त जानकारी मांग सकता है, जिसे अनुमोदन के लिए आवश्यक समझा जाए।
- 8.3 अनुमोदन के लिए आवेदनों पर विचार करते समय प्राधिकृत समिति यह सुनिश्चित करेगा कि देय प्रोत्साहनों की कुल राशि इन दिशानिर्देशों के वित्तीय परिध्यय से अधिक नहीं है।
- 8.4 प्राधिकृत समिति इन दिशानिर्देशों के तहत चयनित आवेदक के निवेश, रोजगार सृजन के संबंध में समय-समय पर समीक्षा करेगा।
- 8.5 प्राधिकृत समिति संवितरण के दावों पर विचार करेगा, जैसा कि परियोजना समीक्षा समिति द्वारा जांच की गई और प्रोत्साहन के संवितरण के लिए सिफारिश की गई है।
- 8.6 अप्रत्याशित जोर दिये जाने वाले मामलों में, प्राधिकृत समिति मामले दर-भारता आधार पर इन दिशानिर्देशों के तहत किसी भी खंड को संशोधित, परिवर्द्धित या वापस ले सकती है।
- 8.7 प्राधिकृत समिति इन दिशानिर्देशों के कार्यकाल के दौरान जब भी आवश्यक समझा जाए, हितधारकों से परामर्श कर सकती है।

9. इन दिशानिर्देशों के तहत अनुमोदन

- 9.1 परियोजना समीक्षा समिति आवेदनों पर कार्रवाई करेगा और अनुमोदन के लिए प्राधिकृत समिति को उपयुक्त सिफारिशें करेगा।
- 9.2 प्राधिकृत समिति परियोजना समीक्षा समिति द्वारा संस्तुत आवेदनों की समीक्षा करेगी। प्राधिकृत समिति में यह शक्ति निहित होगी कि वह आवेदन निरस्त/संशोधित/संस्तुत कर सकेगी और तदनुसार अनुमोदन के लिए उच्च प्राधिकृत समिति (एचईसी) को अप्रेषित करेगी।
- 9.3 दिशानिर्देशों के तहत प्राधिकृत समिति, परियोजनाओं पर चर्चा के दौरान किसी सदस्य के प्रतिनिधि

को भाग लेने की अनुमति नहीं देगी और गणपूर्ति (Quorum) स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्राधिकृत समिति के सदस्यों की किसी भी संख्या की उपस्थिति में आवेदन पर विचार/निरस्त/संशोधन/संस्तुति करने का अधिकार होगा और तदनुसार अनुमोदन के लिए उच्च प्राधिकृत समिति (एचईसी) को अप्रोपेट करने की शक्ति निहित होगी।

9.4 उच्च प्राधिकृत समिति (एचईसी) को निवेश के आवेदन पर अंतिम अनुमोदन का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

आवेदन जमा करने की तारीख से 90 दिनों के भीतर सभी आवेदनों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

9.6 उच्च प्राधिकृत समिति (एचईसी) से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात्, प्राधिकृत समिति 5 कार्य दिवसों के भीतर चयनित आवेदक को आश्वासन पत्र "निश्चय पत्र" जारी करेगा।

9.7 परियोजना शुरू करने के लिए प्राधिकृत समिति द्वारा आश्वासन पत्र जारी करने के 15 दिनों के भीतर आवेदन की स्थिति को संप्रेषित करने, आश्वासन पत्र साझा करने और निवेशक को आमंत्रित करने के लिए परियोजना समीक्षा समिति उत्तरदायी होगी। लैटर ऑफ एस्पोरेंस "निश्चय पत्र" में स्पष्ट रूप से निम्नलिखित का उल्लेख होगा:

- i. आवेदक का नाम
- ii. लक्ष्य क्षेत्र
- iii. प्रस्तावित निवेश एवं रोजगार
- iv. उत्पादन शुरू होने की निर्धारित तिथि
- v. शर्तों के विवरण के साथ प्रोत्साहन अनुसूची
- vi. निवेश, संचालन, कारोबार और रोजगार अनुसूची पर निवेशक की प्रतिबद्धता
- vii. अन्य अनुपालन, वित्तीय प्रोत्साहनों की वार्षिक सीमा आदि
- viii. संयोजी निवेश की वार्षिक सीमा

इस दस्तावेज के अनुलग्नक -8 के तहत एक चित्रमय प्रतिनिधित्व प्रदर्शित किया गया है।

10. पोस्ट अप्रूवल

10.1 परियोजना समीक्षा समिति या परियोजना समीक्षा समिति द्वारा गठित टीम प्रतिबद्ध निवेश के संबंध में जब भी आवश्यक हो, चयनित आवेदक द्वारा की गई परियोजना की प्रगति की निगरानी करेगी।

11. सूचना का सार्वजनिक प्रकटीकरण

11.1 प्रोत्साहनों की गणना, आश्वासन पत्र और संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक डोमेन में साझा नहीं किये जायेंगे। जैसे कि, ऐसी जानकारी की सार्वजनिक पहुँच से:

- i. अन्य फर्मों के साथ हितों का टकराव उत्पन्न हो सकता है।
- ii. राज्य के आर्थिक हित के लिए यह खतरा उत्पन्न कर सकते हैं।
- iii. आवेदक फर्म के साथ उल्लंघन का मामला विकसित हो सकता है।
- iv. आवेदक फर्म की संरक्षित जानकारी का उल्लंघन हो सकता है।

11.2 इन दिशानिर्देशों के तहत उल्लिखित निवेशक, आवेदक और प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए उपयोग की जाने वाली पद्धति अथवा प्रदान की गई जानकारी/दस्तावेजों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संशोधन सहित) की धारा-8 और धारा-9 के तहत संरक्षित किया जाएगा। प्रोत्साहन गणना के लिए एक मार्गदर्शक संरचना अलग से विकसित की जायेगी, जिसे 'सूचना का

अधिकार अधिनियम, 2005 (संशोधन सहित) की धारा -8 और धारा 9 के तहत भी संरक्षित किया जाएगा।

12. प्रोत्साहन अनुसूची की गणना

12.1 आवेदक को वितरित किया जाने वाला वार्षिक प्रोत्साहन वार्षिक प्रोत्साहन की सीमा के अधीन होगा, जैसा कि लैटर ऑफ एस्पोरेंस "निश्चय पत्र" में कहा गया है।

12.2 दिशानिर्देशों के खंड-5 के तहत कुल स्वीकृत प्रोत्साहन की अधिकतम वार्षिक सीमा 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी।

12.3 प्रोत्साहन संवितरण अनुसूची दिशानिर्देशों के खंड-4 के तहत उल्लिखित पात्रता मानदंड को पूरा करने की तारीख से शुरू होगी।

12.4 यह अधिकतम स्वीकृत प्रोत्साहन राशि के संवितरण या 10 वर्ष की शेष समयावधि, जो भी पहले घटित हो, तक जारी रहेगी।

13. प्रोत्साहनों का संवितरण

13.1 इन दिशानिर्देशों के तहत प्रोत्साहन का दावा करने के लिए, आवेदकों को परियोजना समीक्षा समिति के समक्ष प्रोत्साहन के संवितरण के लिए दावे प्रस्तुत करने होंगे। आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दावे सभी प्रकार से पूर्ण हैं और इन दिशानिर्देशों के अनुबंध 4 में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न हों।

13.2 एक आवेदक केवल अर्ध-वार्षिक या वार्षिक आधार पर प्रोत्साहन के संवितरण के लिए दावा प्रस्तुत कर सकता है जो कि अप्रैल से सितंबर और अक्टूबर से मार्च या अप्रैल से मार्च की अवधि में की गई प्रतिबद्धताओं के लिए। किसी भी अवधि के लिए दावा केवल एक बार किया जाएगा जब तक कि यह वापस नहीं लिया जाता है, और उक्त अवधि के लिए बाद के किसी भी भाग के दावे की अनुमति नहीं दी जाएगी।

13.3 परियोजना समीक्षा समिति आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए संवितरण दावे की जांच करेगा। परियोजना समीक्षा समिति पात्रता को सत्यापित करेगा और इन दिशानिर्देशों में निर्धारित विधि और आवेदक को जारी किए गए लैटर ऑफ एस्पोरेंस "निश्चय पत्र" के आधार पर आवेदक को देय प्रोत्साहन का आकलन करेगा।

13.4 परियोजना समीक्षा समिति को प्रोत्साहन के दावे के संबंध में किसी भी दस्तावेज को सत्यापित करने का अधिकार होगा, जिसमें सांविधिक लेखा परीक्षक प्रमाण पत्र और विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, एजेंसियों को प्रस्तुत विवरणी शामिल हैं, लेकिन यह यहीं तक सीमित नहीं है। परियोजना समीक्षा समिति को आवश्यक समझी जाने वाली सीमा तक लेखापरीक्षक प्रमाण पत्र, बैंक विवरण आदि के माध्यम से क्रमशः बिक्री और निवेश के अनुरूप अंतिम वसूली और नियतान भुगतान की जांच करने का भी अधिकार होगा।

13.5 पात्रता और देय प्रोत्साहन राशि, या अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के निर्वहन में किसी भी अन्य मामले के सबंध में किसी भी सदेह के मामले में, परियोजना समीक्षा समिति ऐसे मामले को स्पष्टीकरण के लिए प्राधिकृत समिति को संदर्भित कर सकता है और इस सबंध में प्राधिकृत समिति का निर्णय अंतिम होगा।

13.6 परियोजना समीक्षा समिति इस तरह के दावे की प्राप्ति की तारीख से 90 दिनों के भीतर प्रोत्साहन के संवितरण के दावे को ससाधित करेगा और प्राधिकृत समिति को उचित सिफारिशें करेगा।

13.7 प्राधिकृत समिति परियोजना समीक्षा समिति द्वारा जांच और सिफारिश के अनुसार प्रोत्साहन के संवितरण के दावों पर विचार और अनुमोदन करेगा।

- 13.8 परियोजना समीक्षा समिति आवेदक द्वारा सभी पूर्ण वितरण औपचारिकताओं को पूरा करने और प्राधिकृत समिति से अनुमोदन के बाद स्वीकृत धनराशि का संवितरण करेगा।
- 13.9 प्रोत्साहनों का संवितरण केवल आवेदक के नाम पर प्रीएफएमएस या समायोजन के किसी अन्य तंत्र के माध्यम से प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण के रूप में होगा।
- 13.10 यदि परियोजना समीक्षा समिति या प्राधिकृत समिति इस बात से असंतुष्ट है कि इन दिशानिर्देशों के तहत पात्रता या प्रोत्साहनों का संवितरण तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने या जानकारी के मिथ्याकरण द्वारा प्राप्त किया गया है, प्राधिकृत समिति आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के बाद, संवितरण की तारीख पर प्रचलित 3 साल की एसबीआई एमसीएलआर पर गणना की गई ब्याज के साथ प्रोत्साहन राशि वापस करने के लिए कह सकता है।
- 13.11 खंड 13.10 के तहत उल्लिखित प्रोत्साहनों की वापसी की विफलता के मामले में, दिशानिर्देश लाभ की अवधि के दौरान संयंत्र, मशीनरी और अन्य पूंजीगत संपत्तियों पर पहला अधिकार सरकार के पास निहित रहेगा जिससे सरकार इन पूंजीगत परिसंपत्तियों की नीलामी के माध्यम से संवितरित प्रोत्साहनों की वसूली कर सके।
- 13.12 प्राधिकृत समिति इन दिशानिर्देशों के तहत परियोजना समीक्षा समिति द्वारा प्रोत्साहनों के वितरण के लिए बजटीय प्रावधान करेगा। परियोजना समीक्षा समिति तिमाही आधार पर समेकित राशि के रूप में प्राधिकृत समिति को बजटीय आवश्यकताएं प्रस्तुत करेगा।
- 13.13 परियोजना समीक्षा समिति तिमाही आधार पर प्रोत्साहनों के लिए प्राप्त संवितरण दावों, संवितरित राशि, अस्वीकृति के कारणों, प्रोत्साहनों के संवितरण में देरी के विवरण के साथ प्राधिकृत समिति को सूचना प्रस्तुत करेगा।
14. समीक्षा
- 14.1 इन दिशानिर्देशों की प्रगति और प्रदर्शन के संबंध में प्राधिकृत समिति द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाएगी।
15. अवशिष्ट
- 15.1 एक आवेदक कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के साथ अद्यतन करने के बाद, इन दिशानिर्देशों के कार्यकाल के दौरान अंशधारिता के पैटर्न में किसी भी बदलाव के बारे में परियोजना समीक्षा समिति को सूचित करेगा।
- 15.2 इन दिशानिर्देशों की अवधि के दौरान एक आवेदक के अंशधारित पैटर्न में यदि कोई भी परिवर्तन, जो हिताधिकारी के उत्तराधिकारी की ओर ले जाता है, परियोजना समीक्षा समिति द्वारा प्रोत्साहन के संवितरण पर विचार करने हेतु प्राधिकृत समिति के अनुमोदन के लिए सूचित किया जाएगा।
- 15.3 उत्तराधिकारी के हित के मामले में, आवेदक द्वारा किए गए सभी निवेश, जिसे इन दिशानिर्देशों के तहत अनुमोदन प्रदान किया गया है, पात्रता निर्धारित करने के लिए अनुमोदन के अधीन और प्राधिकृत समिति द्वारा निर्धारित किसी अन्य शर्त के अनुपालन के अधीन, जैसा उचित समझा जाए, विचार किया जायेगा।
- 15.4 पात्र उत्पाद के निर्माण के लिए कोई पुराना/प्रयुक्त/नवीनीकृत संयंत्र, मशीनरी, उपकरण, उपयोगिताओं, या अनुसंधान एवं विकास उपकरण का उपयोग नहीं किया जाएगा।

Notification No: 372 /VII-3-23/166-Udyog/2011 T.C. Dated 22 February, 2023

Annexure

Guidelines for Customized Package under Section-14 of The Uttarakhand Enterprises Single Window Facilitation and Clearance Act, 2012

Guidelines for Customised Package for Industry for promoting investments in Manufacturing and Service Sector

1. Context

- 1.1 With the success of Uttarakhand Investment Summit 2018, lot of businesses showed interest in making investments in Uttarakhand and help in economic development of the State. Memorandum of Understanding (MoUs) were signed for numerous small and large projects, across various sectors. The Government provided financial incentives for these projects through State Government Policies, i.e., Uttarakhand MSME Policy and Mega Industrial policy as well as sector-specific policies. Many of these projects have been grounded and started production. Yet a lot of big projects are still in pipeline for grounding.
- 1.2 It is noted that the proportion of incentives to investment provided under 'Uttarakhand Mega Industrial and Investment Policy 2021' (Mega Policy) decrease as the amount of investment increases. A case study for investment amount of INR 100 and INR 300 crores is placed as Annexure-7. It is evident from the case study that the effect of the subsidies or incentives decreases on percentage terms as the project moves towards higher investment.
- 1.3 It is also to be noted that ultra-mega projects (of investment size of > INR 200 Crores, as defined in Mega Policy), act as a catalyst for industrial growth and attracts ancillary and downstream industries. To facilitate the investment of large projects, States like Andhra Pradesh, Maharashtra, Uttar Pradesh and Rajasthan provide customised incentives on a case-to-case basis. In Uttarakhand context, these projects may be defined as Ultra Mega or special category projects. Such industries may be given preferential or customized offers to fuel industrial growth within the State.
- 1.4 Uttarakhand's Single Window Act 2012 also has a provision for providing customised package under Section-14 but it hasn't been used, due to a lack of guidelines and a notified procedure for implementation. It is thus decided that guidelines may be formulated to operationalise the provision of customised incentives for large size projects. As defined in Mega Policy, these guidelines are applicable only on Ultra Mega Project, i.e., on investments of more than INR 200 Crores. These guidelines are being issued for effective and smooth implementation of this provision on providing customised package.

2. Definition

- 2.1 **The Guidelines:** "Guidelines for Customized Package under Section-14 of The Uttarakhand Enterprises Single Window Facilitation and Clearance Act, 2012."
- 2.2 **Applicant:** For the purpose of these Guidelines, applicant shall be an entity registered in India, as per eligibility criteria, proposing to manufacture goods in the state or provide services from the state and is making an application for seeking customised

incentive under these Guidelines. The applicant shall make a threshold investment in any Greenfield or expansion/ diversification in a brown field project in the state.

- 2.3 Application:** Application submitted by an applicant to the Project Review Committee (PRC) as per the Application Form prescribed under these guidelines containing requisite information, along with supporting documents and application fee.
- 2.4 Application Acknowledgement Date:** The date on which an application is acknowledged by the PRC after carrying out initial scrutiny in this regard.
- 2.5 Application Approval Date:** The date on which the Letter of Assurance "Nishchaya Patra" under the Guidelines is issued by the Empowered Committee (EC).
- 2.6 Base Year:** Year in which application is submitted, will be considered as Base year.
- 2.7 Brownfield project:** Any eligible project, above threshold limits, either operative or non-operative, where fresh investment is being made, either by current owner or new owner. Separate records shall however be maintained for the expansion of an existing facility for the purpose of these Guidelines.
- 2.8 Date of Commercial production:** The date on which the applicant raises the first GST invoice for the sale of Eligible Product(s) manufactured under the Guidelines.
- 2.9 Employment:** It means the number of direct jobs created in the production process or with related activities beginning from when materials enter a production facility and up until the resultant manufactured goods leave the production facility. In case of services, number of jobs will be calculated as people employed by the applicant and not affiliates or by third parties. Such employment shall include on-roll, contractual and apprentice workforce employed within the State only.
- 2.10 Project Review Committee (PRC):** To review and scrutinize applications, one member Committee has been constituted under the Chairmanship of Secretary, Industries. Director General/ Commissioner and Director, Industries may support Secretary to analyse potential economic impact, support in gathering additional information, understand and apprise about the financials regarding the project, etc. The PRC shall evaluate the project details furnished by the application and may include additional information required as well as site visits. PRC shall furnish its recommendations to Empowered Committee. Secretary, Industries may seek/ involve other experts from the Central/ State Governments or otherwise e.g., legal, information technology, finance, other sectors, etc. as and when required.
- 2.11 Empowered Committee (EC):** The composition of the Empowered Committee will be as follows:

| Member | Designation in Committee |
|---|-------------------------------|
| Chief Secretary, Government of Uttarakhand | Chairman, Empowered Committee |
| Secretary, Finance, Government of Uttarakhand | Member |
| Secretary, Industries, Government of Uttarakhand or Chairman Project Review Committee | Member Secretary |

- 2.12 High Empowered Committee (HEC):** The composition of the High Empowered

Committee will be as follows.

| Member | Designation in Committee |
|--|--------------------------|
| Chief Minister, Government of Uttarakhand | Chairman |
| Minister, Industrial Development, Government of Uttarakhand | Member |
| 2.13 Financial Year: Financial Year begins on the 1st April of a year and ends on 31st March of the following year. | |
| 2.14 Force Majeure: Extraordinary events or circumstances beyond human control such as events described as an act of God (like a natural calamity) or events such as a war, strike, public health emergency, riots, crimes (but not including negligence or wrongdoing, predictable seasonal rain and any other events specifically excluded) | |
| 2.15 Greenfield Project: A eligible project wherein minimum threshold investment is proposed to be made by the applicant under these Guidelines in a new production/ services facility or the same investment amount of initial investment for expansion purpose. Separate records are to be maintained for the purpose of these Guidelines. | |
| 2.16 Incentive: Incentive is the financial benefit to be provided to each selected applicant based on the provisions of these Guidelines. | |
| 2.17 Eligible Investment: Eligible Investment shall mean expenditure incurred on new Plant, i.e., Building, Machinery, Equipment and Associated Utilities (including parts, accessories, components, and spares thereof) of the same, used in the design, manufacturing, assembly, testing, packaging or processing of any of manufactured goods or services delivered. Associated utilities would also include IT and ITES infrastructure related to manufacturing including servers, software and ERP solutions. Including transport, installation and insurance charges of Plant, Machine and Equipment. | |
| 2.18 Ineligible Investment: The expenditure incurred on land required, land developer working capital for the project/unit shall not be considered as part of threshold investment limit, under these Guidelines. | |
| 2.19 Competent Authority: PRC or any other authority(ies) appointed by EC, refers to the competent authority to act on its behalf for receipt and appraisal of applications, verification of eligibility and examination of disbursement claims through any method/document deemed appropriate and for managing the above-mentioned in accordance with these guidelines. | |
| 2.20 Threshold Investment: The minimum investment to be made for eligibility under these Guidelines as specified under eligibility criterion of these guidelines. | |
| 2.21 Threshold Employment: The minimum number of employments to be created for eligibility under these Guidelines as specified under eligibility criterion of these guidelines. | |

3. Validity

- 3.1 These Guidelines will come into force from the date of issue of the notification and will be effective for the next five years.

3.2 The right to provide any kind of relaxation in the provisions of these Guidelines will be vested in the Government.

3.3 These guidelines can be amended by The Chief Minister at any time, basis on the recommendations made by Empowered Committee, as and when required.

4. Eligibility Criterion and Selection of Applicant

4.1 Eligibility for Application

4.1.1 The firm should be registered with Registrar of Companies under 'The Companies Act, 2013' (including the amendments). Startups recognized by Government of India or any State Government shall also be eligible to apply.

4.1.2 Investment into manufacturing and service sector, both are eligible to apply for the benefits.

4.1.3 The applicant should not have been declared as bankrupt or wilful defaulter or defaulter or reported as fraud by any bank or financial institution or non-banking financial company.

4.1.4 Minimum Threshold Limits:

4.1.4.1 Investment: Projects with 'Eligible Investment' of INR 200 Crores or more shall be eligible for the benefits under these Guidelines, OR

4.1.4.2 Employment: The applicant entity should be able to generate direct employment of 500 personals/ annum, starting from the first year of Operations.

4.1.5 For the purpose of determining the eligibility of disbursement of approved fiscal incentives to the applicant under these Guidelines; the applicant shall be eligible to avail incentives after meeting the Minimum Threshold Limits criteria mentioned under clause 4.1.4 and the commencement of:

4.1.5.1 Production of the project for manufacturing sector units.

4.1.5.2 First sale recognised on Uttarakhand SGSIT based invoice for service sector units.

4.1.6 Eligibility under these Guidelines shall not affect eligibility under any other policy and vice versa.

4.1.7 Applicants availing incentives under customised packages are not eligible to avail incentives under other policies notified by the Government of Uttarakhand.

4.1.8 Eligible Applicant can apply for incentives being provided under any scheme of Government of India, subject to the total incentives being under the maximum limit of 100% of Eligible Investment as per clause 2.16

4.2 Selection

4.2.1 The PRC will evaluate the application basis on which it will recommend the project for approval to EC. Checklist for evaluation is placed at Annexure 8.

4.2.2 PRC has the right to reject an application even if the applicant meets the

minimum investment criteria. The PRC will have to provide a relevant reason for the rejection of the application. The reason for rejection will not be shared with the applicant but will be documented for the purpose of review for EC.

5. Terms & Conditions for Eligible Investment Amount

5.1 General Terms & Conditions

5.1.1 As the Non-Disclosure Agreement is done by other State Governments before providing these customised packages, the information regarding the incentive amount being given to the projects will be between the Government and the party itself. If the party is found to be in violation of the NDA, then the party will be liable to return the incentive being provided.

5.1.2 Eligible Investment shall be considered for determining eligibility under the Guidelines provided such Investment is made after issuance of these Guidelines.

5.1.3 Expenditure on consumables and raw material used for manufacturing shall not be considered as Investment.

5.1.4 The date of purchase invoice would be considered as the date of investment under the Guidelines.

5.1.5 Billing address for any part of eligible investment should be of a location in the State of Uttarakhand.

5.1.6 The applicant unit shall enter into an operational lock-in period by signing an agreement, which is minimum of 15 years starting from the date of commencement of:

5.1.6.1 Production of the project for manufacturing sector units.

5.1.6.2 First sale recognised on Uttarakhand SGST based invoice for service sector units

5.2 Terms & Conditions for Plant, Machinery and Equipment

5.2.1 Expenditure incurred on new Plant, Machinery and Equipment as defined in Clause 2.16 of these guidelines shall be considered as Investment for determining eligibility under these Guidelines.

5.2.2 New Plant, Machinery and Equipment should be purchased/leased in the name of the applicant. In cases where these are being leased, the lease should be in the nature of a financial lease within the meaning of Accounting Standard 19 — Leases or Indian Accounting Standard (Ind-AS) 116 Leases, as may be applicable to the applicant, as notified by Ministry of Corporate Affairs or any other appropriate authority from time to time.

5.2.3 Plant, Machinery and Equipment should be procured/leased through legally valid documents after payment of applicable taxes and duties.

6. Application procedure

6.1 An applicant shall submit an undertaking in the format of Annexure 1 consenting audit of their manufacturing site/offices for verification of information/data submitted along

with the application.

- 6.2 On receipt of an application in the prescribed format, Project Review Committee will conduct an examination as to whether the application *prima facie* meets the eligibility criterion as prescribed in these guidelines. The aforesaid *prima facie* examination shall be completed within 15 working days from the date of receipt of the original application or any subsequent submission of the revised application if the original filing was returned as incomplete earlier.
- 6.3 In case, on the above-mentioned examination, an application is found to be incomplete, Project Review Committee shall inform the applicant accordingly within 15 working days of receipt of the application.
- 6.4 For an eligible application, Project Review Committee shall issue an acknowledgement of receipt of the application within 15 working days of receipt of the application along with an Non-Disclosure Agreement, that needs to be signed by both the parties (Applicant and PRC).
- 6.5 This acknowledgement shall not be construed as approval or Letter of Assurance under these Guidelines. In case, where on examination it is found that an original or a revised application does not *prima facie* meet the criteria as prescribed, the Project Review Committee shall inform the applicant accordingly within 15 working days of receipt of application.

7. Project Review Committee (PRC)

- 7.1 These Guidelines will be implemented through a Project Review Committee (PRC) which will be responsible for providing secretarial, managerial and implementation support and carrying out other responsibilities as assigned by Empowered Committee (EC) from time to time.
- 7.2 The PRC shall be responsible for:
 - 7.2.1 Receipt of applications, examination and processing of applications and issuing acknowledgements.
 - 7.2.2 Fortnight submission to EC, the status of applications received and processed under these Guidelines.
 - 7.2.3 Making appropriate recommendations to the EC for approval of applications under these Guidelines.
 - 7.2.4 Verification of thresholds for determining eligibility for disbursement of incentive.
 - 7.2.5 Examination of claims for disbursement of incentive and making appropriate recommendations to the EC.
 - 7.2.6 Verification of the reconciliation of disbursement claims with prescribed documents.
 - 7.2.7 Compilation of data regarding progress and performance of these Guidelines through Quarterly Review Reports as per Annexure 3 and other information/documents.

- 7.3 The PRC may request additional information, details and documents from the applicant as deemed necessary.
- 7.4 The PRC will have the right to carry out a physical inspection of an applicant's manufacturing units and offices through a site visit.
- 7.5 The PRC is empowered to form a team of experts in subject matter, project management as and when required to review, monitor, manage and implement the benefits availed by the investors under these Guidelines and to carry out the administrative work.
- 7.6 Efforts will be made to convince the applicant to optimise use of existing policies and land allotment procedure in the state. In case, the project is fitting into the eligibility criteria of these guidelines, project proponent will be guided to make an application.
- 7.7 Total fiscal incentives up to 100% of eligible investment amount as per clause 2.16 with Terms & Conditions as per clause 5 of The Guidelines, may be provided; with a maximum limit of estimated revenue accrued to the state through various State Taxes, Stamp Duty and other Levies in 10 years of period from the date of start of operations (including taxes and levies paid during capital investment or grounding of the project).
- 7.8 Preference will be to provide incentive by way of reimbursements to ensure that the commitments made by the investor have been implemented. However, as the case warrants, incentives may also be provided on capex invested.

8. Empowered Committee (EC)

- 8.1 The EC shall meet as often as necessary to ensure timely consideration of applications and disbursement claims and conduct a periodic review of these Guidelines
- 8.2 The EC will consider applications, as recommended by the PRC, for approval under these Guidelines. The EC may seek such additional information, as considered necessary for approval.
- 8.3 The EC while considering applications for approval shall ensure that the total amount of incentives payable does not exceed the Financial Outlay of these Guidelines.
- 8.4 The EC will conduct a periodic review of the selected applicant with respect to their investments, employment generation under these Guidelines.
- 8.5 The EC will consider claims for disbursement, as examined and recommended by the PRC, for disbursement of incentive.
- 8.6 In case of a Force Majeure Event, the EC may amend, modify or withdraw any Clause under these Guidelines on case-to-case basis.
- 8.7 The EC may hold stakeholder consultation as and when deemed necessary during the tenure of these Guidelines.

9. Approval under these Guidelines

- 9.1 The PRC shall process the applications and make appropriate recommendations to the EC for approvals.
- 9.2 The Empowered Committee will scrutinize the applications recommended by the Project Review Committee. The Empowered Committee shall be vested with the

power to reject/modify/recommend the application and accordingly forward it to the Higher Empowered Committee (HEC) for approval.

- 9.3 The Authorized Committee, under the guidelines, shall not allow the representative of any member to participate during the discussion on the projects and there is no need to establish a quorum. The Empowered Committee shall have the power to consider/reject/modify/recommend the application in the presence of any number of members and accordingly shall have the power to forward it to the Higher Empowered Committee (HEC) for approval.
- 9.4 The High Empowered Committee (HEC) reserves the right of final approval on the investment application.
- 9.5 All the applications will be finalized within 90 days from the date of application submission.
- 9.6 After getting the approval from the High Empowered Committee (HEC), the Empowered Committee will issue the letter of assurance "Nischay Patra" to the selected applicant within 5 working days.
- 9.7 The PRC shall be responsible for communicating application status, sharing the Letter of Assurance and inviting investor within 15 days of issuing the Letter of Assurance by EC, for project commencement. The Letter of Assurance "Nishchaya Patra" shall clearly State the following:

- i. Name of Applicant
- ii. Target Sector
- iii. Proposed Investment and Employment
- iv. Scheduled date of commencement of production
- v. Incentive Schedule with details on conditions
- vi. Investor's commitment on investment, operations, turnover and employment schedule
- vii. Other compliances, annual ceiling offiscal incentives, etc.
- viii. Yearly threshold of cumulative Investment.

A graphical representation is demonstrated under Annexure-6 of this document.

10. Post Approval

- 10.1 PRC or the team formed by PRC shall monitor the progress of the project made by the selected applicant as and when required with respect to investment committed.

11. Public Disclosure of the Information

- 11.1 The calculation of incentives, the Letter of Assurance and related documents are not subject to share in public domain. As, public access of such information may:
 - i. Create conflict of interest with other firms,
 - ii. Become threat to the economic interest of the State,
 - iii. Develop matter of infringement with the applicant firm,
 - iv. Violate the protected information of the applicant firm,

- 11.2 The information/ documents provided by the investor, applicant; and procedures, methodology used to implement, mentioned under these Guidelines shall be protected under the Section-8 and Section-9 of 'The Right to Information Act, 2005 (including amendments). A guiding framework for incentive calculation shall be developed separately which shall also be protected under the Section-8 and Section-9 of 'The Right to Information Act, 2005 (including amendments).

12. Calculation of Incentive Schedule

- 12.1 The annual incentive to be disbursed to the applicant shall be subject to the ceiling of the annual incentive, as stated in the Letter of Assurance "Nishchaya Patra".
- 12.2 The maximum annual limit shall be 10% per annum of total approved incentive under the clause 5 of The Guidelines.
- 12.3 The incentive disbursement schedule shall start from the date of fulfilling the Eligibility Criteria mentioned under the clause 4 of The Guidelines
- 12.4 It shall be continued till the disbursement of maximum approved incentive or remaining time period of 10 years; whichever event occurs earlier

13. Disbursement of Incentives

- 13.1 For claiming incentives under these Guidelines, applicants will be required to submit claims for disbursement of incentives to the PRC. Applicants must ensure that the claims are complete in all respects and are accompanied by all the required documents as per the format prescribed in Annexure 4 of these guidelines.
- 13.2 An applicant may submit a claim for disbursement of incentive only on a half-yearly or annual basis that is for the commitments made in the period of April to September and October to March or April to March. Claims for any period shall be made only once unless withdrawn, and no subsequent part claim shall be allowed for the said period.
- 13.3 The PRC will examine the disbursement claim as submitted by an applicant. The PRC shall verify eligibility and assess incentive payable to an applicant based on the method laid down in these guidelines and the Letter of Assurance "Nishchaya Patra" issued to the applicant.
- 13.4 The PRC will have the right to verify any document(s) in relation to the claim for incentive including but not limited to statutory auditor certificates and returns furnished to various Ministries, Departments, Agencies. The PRC shall also have the right to examine the end realization and settlement payments corresponding to sales and investment respectively by way of auditor's certificate, bank statements etc. to the extent deemed necessary.
- 13.5 In case of any doubt with respect to determining eligibility and incentive amount due, or any other matter in the discharge of its duties and responsibilities, the PRC may refer such matter to EC for clarification and the decision of EC shall be final in this regard.
- 13.6 The PRC shall process the claim for disbursement of incentive within 90 days from the date of receipt of such claim and make appropriate recommendations to the EC.
- 13.7 The EC will consider and approve claims for disbursement of incentive, as examined and recommended by the PRC.

- 13.8 The PRC shall disburse funds after completion of all pre-disbursal formalities by the applicant and approval from EC.
- 13.9 The disbursement of incentives will be in the form of Direct Bank Transfer through PFMS or any other mechanism of adjustment in the name of the applicant only
- 13.10 If the PRC or EC is dissatisfied that eligibility under these Guidelines or disbursement of incentives have been obtained by misrepresentation of facts or falsification of information, EC may ask the applicant to refund the incentives along with interest calculated at 3 years SBI MCLR prevailing on the date of disbursement, compounded annually, after giving an opportunity to the applicant of being heard.
- 13.11 In case of failure of refund of incentives as mentioned under the clause 13.10; The first right on Plant, Machinery and other Capital Assets, shall remain with the Government during the period of Guidelines benefits. Whereby the Government may recover the incentives disbursed, through auction of these capital assets.
- 13.12 EC shall make budgetary provisions for disbursal of incentives by the PRC under these Guidelines. The PRC will submit budgetary requirements to EC as a consolidated amount on quarterly basis.
- 13.13 The PRC shall furnish information to EC with details of disbursement claims received for incentives, amount disbursed, reasons for rejection, delay in disbursement of the incentives on a quarterly basis.
14. **Review**
- 14.1 Periodic reviews will be undertaken by the EC with respect to progress and performance of these Guidelines.
15. **Residual**
- 15.1 An applicant shall intimate the PRC of any change in the shareholding pattern during the tenure of these Guidelines, after updating with the Registrar of Companies (RoC).
- 15.2 Any change in the shareholding pattern of an applicant leading to a successor-in-interest during the tenure of these Guidelines, shall be intimated by PRC for approval of the EC to consider for disbursal of incentives.
- 15.3 In case of a successor-in-interest, all Investment undertaken by the applicant to whom approval was accorded under these Guidelines, would be considered for determining eligibility, subject to approval and compliance with any other condition stipulated by the EC, as may be deemed appropriate.
- 15.4 No second hand/used/refurbished plant, machinery, equipment, utilities, or R&D equipment shall be used to manufacture the eligible product.

अधिसूचना

22 फरवरी, 2023 ई०

संख्या 373/VII-3-23/04(03)-एम0एस0एम0ई0/2020-राज्य में निजी औद्योगिक क्षेत्रों के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में विशेष औद्योगिक क्षेत्रों, निर्यात क्षेत्रों, थीम पार्कों, जैव प्रौद्योगिकी पार्कों, एकीकृत औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना में निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से "निजी औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों की स्थापना हेतु नीति, 2023" (संलग्नक) प्रख्यापित किये जाने हेतु एतद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अधिसूचना संख्या 373/VII-3-23/04(03)-एम०एस०एम०ई०/2020, दिनांक 22 फरवरी, 2023 का
सलग्नक

अनुसूचक

उत्तराखण्ड में निजी औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों की स्थापना हेतु नीति-2023

1- पृष्ठभूमि और दृष्टि:

उत्तराखण्ड सरकार राज्य में एकीकृत औद्योगिक पार्कों के विकास के माध्यम से औद्योगिक उपयोग के लिए निजी भूमि के उपयोग को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है। औद्योगिक पार्क आर्थिक गतिविधियों का केंद्र हैं और राज्य में मूल्यवर्धन और रोजगार सृजन की दिशा में भारी योगदान देते हैं।

राज्य सरकार त्वरित औद्योगिक विकास हेतु राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भूमि की कमी का सामना कर रही है। उत्तराखण्ड में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए निजी प्रवर्तकों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है। उत्तराखण्ड राज्य में विशेष औद्योगिक क्षेत्रों, निर्यात क्षेत्रों, थीम पार्कों, जैव प्रौद्योगिकी पार्कों, एकीकृत औद्योगिक सम्पदाओं/क्षेत्रों की स्थापना में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 11/औ०वि०/07-उद्योग/2004 दिनांक 27 जनवरी, 2004 तथा शासनादेश संख्या 940/औ०वि०/07-उद्योग/2004-06 दिनांक 09 नवम्बर, 2004 से निजी क्षेत्र में निजी औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों की स्थापना के लिए नीति प्रख्यापित की गयी थी। साथ ही अधिसूचना संख्या 488/VII-II/08/08 द्वारा अधिसूचित विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2008 के अंतर्गत राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में निजी औद्योगिक आस्थान की स्थापना के लिए भूमि की न्यूनतम सीमा/ आवश्यकता 2 एकड़ निर्धारित की है। इसमें औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं, जैसे बिजली, पानी, सड़क, कनेक्टिंग रोड और ड्रेनेज सिस्टम के विकास के लिए किये गये कुल व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम 50 लाख रुपये तक की प्रतिपूर्ति औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र के प्रवर्तकों को अनुदान के रूप में किये जाने का प्राविधान किया गया है।

प्रदेश में 3113.30 एकड़ भूमि पर कुल 49 निजी औद्योगिक आस्थानों को अधिसूचित किया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा 50 करोड़ रुपये से अधिक के अचल पूंजी निवेश की 26 मेगा परियोजनाओं के लिए 446.48 एकड़ भूमि विशेष औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित की गयी है।

वर्ष 2004 में प्रख्यापित नीति में निजी क्षेत्र के औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं पर कोई वित्तीय प्रोत्साहन नहीं दिया गया था। पर्वतीय क्षेत्र के लिए प्रख्यापित विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2008 में निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले औद्योगिक आस्थानों में आधारभूत सुविधाओं के विकास पर होने वाले व्यय पर वित्तीय प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया था।

उत्तराखण्ड में निजी औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों/पार्कों की स्थापना हेतु नीति 2022 निम्नानुसार प्रस्तावित की जा रही है:

2- उद्देश्य:

- i. निजी क्षेत्र में औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों की स्थापना को बढ़ावा देकर राज्य में निवेश आकर्षित करना।
- ii. उद्योगों की स्थापना के लिए औद्योगिक भूखण्डों/भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- iii. औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- iv. राज्य में मینی/बृहत औद्योगिक आस्थानों एवं क्षेत्र विशिष्ट पार्कों की स्थापना।
- v. औद्योगिक बुनियादी ढांचे का विकास करके सतुलित और नियोजित औद्योगिक विकास सुनिश्चित करना।

3- परिभाषा:

- i. 'औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र' का तात्पर्य उस आस्थान/क्षेत्र से है, जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से ऐसा आस्थान/क्षेत्र घोषित किया जाय।
- ii. 'सुविधा' के अन्तर्गत सड़क, जल-सम्भरण, सड़क पर रौशनी, विद्युत सम्भरण, सीवर व्यवस्था, जलोत्सारण, औद्योगिक उच्छिष्ट पदार्थ और कूड़ा-करकट का संग्रह, शोधन और निस्तारण तथा ऐसा अन्य सामुदायिक कार्य, सेवा या सुविधा है, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस नीति के क्रियान्वयन के लिए सुविधा के रूप में विनिर्दिष्ट करे।
- iii. 'अध्यासी (Occupier)' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है, (जिसमें कोई फर्म या व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, सम्मिलित है) जिसके अध्यासन में औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र के भीतर कोई स्थल या भवन है और अध्यासी के अन्तर्गत उसका उत्तराधिकारी और समनुदेशिती (Legal Heirer & Assigns) भी है।
- iv. 'अन्तरिती (Transferee)' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है (जिसमें कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, भी सम्मिलित है) जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी भी रीति से भूमि या भवन अन्तरित किया जाय और अन्तरिती के अन्तर्गत उसका उत्तराधिकारी और समनुदेशिती (Legal Heirer & Assigns) भी है।
- v. शब्द और पदावलि 'भवन', 'विकास', 'भवन के परिनिर्माण' और 'भूमि' के वही अर्थ होंगे जैसा कि उत्तराखण्ड सामान्य औद्योगिक विकास विनियमावली, 2022 (UGIDCR-2022) में परिभाषित किया गया है।
- vi. 'औद्योगिक आस्थान की व्यवसायिक गतिविधि की शुरुआत' का अर्थ है, जिस तिथि को प्रवर्तक द्वारा व्यवसायिक पैमाने पर आस्थान में अवस्थापना सुविधाओं के संस्थापन के पश्चात औद्योगिक भूखण्डों का वाणिज्यिक रूप से विपणन प्रारम्भ किया गया हो, जिसके लिए प्रवर्तक को अधिकृत या अनुमोदित किया गया है।
- vii. 'औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र की स्थापना' का अर्थ सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृत औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र के विनियमन की तारीख से है।
- viii. 'विभाग' का अर्थ है सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- ix. प्राधिकृत समिति या राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति का अर्थ उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम, 2012 (अधिनियम संख्या 05/2013) में निर्दिष्ट प्राधिकृत समिति से है।

- x. "मैदानी क्षेत्र" का अर्थ है उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम नीति-2015 (यथासंशोधित- 2016, 2018, 2019, 2020 व 2021) के अनुसार श्रेणी सी और श्रेणी डी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र।
- xi. "पर्वतीय क्षेत्र" का अर्थ उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम नीति-2015 (यथासंशोधित- 2016, 2018, 2019, 2020 और 2021) में वर्गीकृत श्रेणी ए, श्रेणी-बी और श्रेणी बी+ के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों/जिलों से है, जैसा कि कार्यालय द्वाप संख्या 184/VII-2-15/146-MSME/2013 दिनांक 31 जनवरी 2016 और कार्यालय द्वाप संख्या 544/VII-2-16/146-MSME/2013 दिनांक 22 मार्च, 2016 में परिभाषित किया गया है।
- xii. "इण्डस्ट्रियल पार्क/इस्टेट" का अर्थ है एक ऐसी औद्योगिक सम्पदा, जिसका विकास औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए किसी अच्छी या सेवा के निर्माण के लिए किया गया हो और जिसमें विकसित भूखण्ड, आंतरिक सड़कें, जल वितरण सुविधाएं, सीवेज संग्रह और उपचार, बिजली वितरण, संचार सुविधा जैसी बुनियादी सुविधाएं हों।
- xiii. "औद्योगिक इकाई" का अर्थ है सरकार द्वारा विभागीय रूप से संचालित इकाई के अलावा कोई औद्योगिक उपक्रम अथवा सेवा क्षेत्र इकाई, जो कि वस्तु और सेवा कर के तहत एक पंजीकृत व्यापार उद्यम है।
- xiv. "मिनी औद्योगिक आस्थान" का तात्पर्य प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम 2 एकड़ या उससे अधिक भूमि पर विकसित औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र से है।
- xv. "नीति" का अर्थ निर्जो औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र की स्थापना हेतु प्रोत्साहन नीति-2022 है।
- xvi. रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के तहत परिभाषित "व्यक्ति"।
- xvii. रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के तहत परिभाषित "प्रमोटर"।
- xviii. "सैक्टर स्पेसिफिक इण्डस्ट्रियल पार्क" का तात्पर्य सैक्टर विशेष के उद्योगों के लिए चिन्हित विशिष्ट पार्क, यथा:
- परिधान फाइबर और कपड़ा पार्क
 - आईटी पार्क/सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क
 - जेम एंड ज्वेलरी पार्क
 - फूड पार्क
 - बायो-टैक
 - आयुष और वेलनेस पार्क
 - ऑटोमोबाइल अनुषंगी उद्योग पार्क
 - अरोमा पार्क
 - एयरोस्पेस एवं रक्षा पार्क
 - नॉलेज पार्क
 - फिल्म सिटी/क्षेत्र

l) सर्विस सेक्टर पार्क (एयरोसिटी, मेडिसिटी, एजुसिटी और ऐसा पार्क, जिसमें फिल्म निर्माण, मनोरंजन, शिक्षा, चिकित्सा सुविधा आदि व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के लिए इकाईयों की स्थापना की जायेगी)।

m) कोई अन्य विशिष्ट सेक्टर पार्क

xvix. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 के तहत परिभाषित "एस्करो एजेंट"।

4- नीति की वैधता अवधि:

- i. यह नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रवृत्त होगी और आगामी पांच वर्ष तक प्रभावी रहेगी।
- ii. राज्य सरकार इस नीति में किसी भी समय मा0 मंत्रिमण्डल के अनुमोदन पर आवश्यकतानुसार संशोधन अथवा परिवर्द्धन कर सकती है।
- iii. इस नीति के प्राविधानों में किसी भी प्रकार की शिथिलता प्रदान किये जाने का अधिकार शासन में निहित रहेगा।

5- पात्रता एवं प्रक्रिया:

- i. निजी औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र की स्थापना एक व्यक्तिगत संस्थापक/विकासकर्ता/साझेदारी फर्म/एलएलपी/कंपनी या कंपनी अधिनियम/सोसाइटी अधिनियम/सीमित देयता भागीदारी, संयुक्त उद्यम, सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड अथवा लैण्ड एग्रीगेटर (सभी संबंधित भूस्वामियों की लिखित सहमति के साथ) के रूप में विधिक रूप से पंजीकृत कम्पनी/संस्था द्वारा की जा सकती है।
- ii. औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र की स्थापना के लिए प्रमोटर को भूमि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। आस्थान की स्थापना के लिए विभिन्न विभागों से वांछित स्वीकृतियों/अनुज्ञां/अनापत्ति तथा भूमि के अर्जन हेतु उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा-154 (4)(3)(क)(v) के अन्तर्गत औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि क्रय करने की अनुमति प्राप्त करने में विभाग द्वारा सहयोग प्रदान किया जायेगा।
- iii. इस नीति के अन्तर्गत निम्नांकित प्रतिभागियों को सहायता प्रदान की जायेगी
 - a) विनिर्माणक/अवस्थापना क्षेत्र की इकाईयां।
 - b) एंकर इन्वेस्टर्स।
 - c) बड़ी संख्या में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सदस्यता वाले उद्योग संघ।
 - d) उद्योगों का समूह।
 - e) संयुक्त उपक्रम, पीपीपी मोड में स्थापित संस्था।
 - f) इस नीति के खण्ड 5(i) में उल्लिखित पात्र इकाई/संस्था/कम्पनी।
- iv. परियोजना भूमि:
 - a) निवेशक/प्रवर्तक अपने स्रोतों से भूमि की व्यवस्था स्वयं करेगा।

- b) यदि निवेशक सिडकुल से भूमि प्राप्त करना चाहता है, निवेशक को भूमि की आवश्यकता के लिए सिडकुल को एक प्रस्ताव देना होगा। जिससे सिडकुल बोर्ड प्रस्ताव पर नियम और शर्तों (अर्थात् भूमि पट्टे की अवधि, उप-पट्टा आदि) के साथ निर्णय लेगा।
- c) लैण्ड एग्रीगेटर्स के मामले में सिडकुल प्रमोटर द्वारा किसी भी लॉट को वापस लेने से पहले भुगतान किए गए वित्तीय दायित्वों को सुनिश्चित करने के लिए एक नियामक के रूप में कार्य करने हेतु प्रमोटर के साथ अनुबन्ध करेगा।
- v. निजी औद्योगिक आस्थान की स्थापना के लिए मैदानी क्षेत्र में कम से कम 30 एकड़ और पर्वतीय क्षेत्र में कम से कम 2 एकड़ या इससे अधिक भूमि होनी आवश्यक है।
- vi. निजी क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क/बायोटेक्नोलॉजी पार्क के विकास/स्थापना/विनियमन के लिए सीडा के प्रचलित भवन उप-नियमों के अनुसार न्यूनतम 18,000 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्रफल (Builtup Area) होना आवश्यक है।
- vii. प्रस्तावित भूमि पूरी तरह से प्रवर्तक के कब्जे में होनी चाहिए और किसी भी अतिक्रमण से मुक्त होनी चाहिए।
- viii. निजी क्षेत्र के औद्योगिक आस्थानों के विकास हेतु सीडा के मानदण्डों का पालन करना होगा।
- ix. a) प्रमोटर सिडकुल के नियमों और शर्तों के साथ सिडकुल के निदेशक मंडल की सहमति से सिडकुल ब्रांड छवि का उपयोग कर सकते हैं, सिडकुल मानकों के अनुसार पार्क के विकास, कार्यान्वयन और विनियमन के लिए प्रबन्धन शुल्क ले सकेगा।
- b) औद्योगिक पार्क के बिक्री योग्य क्षेत्र में भूखण्डों का आवंटन, हस्तांतरण और विभाजन, प्रमोटर, सिडकुल और एस्करो एजेंट के बीच एक त्रि-पक्षीय समझौते के माध्यम से किया जाएगा।
- x. प्रवर्तक/संगठन/कम्पनी द्वारा औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न विभागों से वांछित अनुमोदन/स्वीकृति/अनापत्ति/अनुज्ञा स्वयं प्राप्त की जायेगी, जिसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग सिंगल विण्डो क्लीयरेंस सिस्टम के प्राविधानों के तहत अनुमोदन/अनुमति/अनुमोदन/अनापत्ति प्राप्त करने में अपेक्षित सहयोग प्रदान करेगा।
- xi. औद्योगिक आस्थान/क्षेत्रों के विकास हेतु General Industrial Development Control Regulations- 2022/Unified Building Bye-laws में भवन निर्माण एवं भूमि उपविभाजन तथा औद्योगिक आस्थानों के लिए निर्धारित भू-उपयोग मानकों का अनुपालन किया जायेगा, जिसके लिए उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (SIDA), नियामक प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा।
- xii. ऐसे औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं की देख-रेख, नालियों, आन्तरिक सड़कों के रख-रखाव, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य नागरिक सुविधायें प्रदान करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित आस्थान की प्रवर्तक संस्था/कम्पनी/स्वामी की होगी।

- xiii. निजी औद्योगिक आस्थान में औद्योगिक भूखण्डों की दरों का निर्धारण एवं विपणन स्वयं आस्थान के प्रवर्तक/निदेशक मण्डल द्वारा किया जायेगा। इसमें राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं होगी।
- xiv. आस्थान के प्रवर्तकों द्वारा आवंटियों के साथ एक अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसमें आस्थान में उपलब्ध करायी जाने वाली सभी प्राथमिक अवस्थापना सुविधाओं, भूखण्ड की दरों, रख-रखाव आदि के लिए प्रतिवर्ष ली जाने वाली धनराशि तथा शर्तों के बारे में स्पष्ट रूप से विवरण दिया जाना आवश्यक होगा।
- xv. (1) निजी औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र की स्थापना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन/विनियमन की प्रक्रिया दो चरणों की होगी:
 - a) प्रथम चरण में औद्योगिक आस्थान की स्थापना के इच्छुक उद्यमी/संस्था/कंपनी के आवेदन पर ही सैद्धांतिक स्वीकृति दी जाएगी।
 - b) दूसरे चरण में आस्थान/क्षेत्र के लिए अधिग्रहित भूमि पर SIDA द्वारा अनुमोदित लेआउट योजना के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आस्थान की स्थापना के लिए जारी सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र के भीतर शर्तों और प्रतिबंधों का पूरी तरह से पालन किया गया है, इस संबंध में औपचारिक अधिसूचना जारी की जाएगी।
- (2) सभी पीपीपी/संयुक्त उद्यम औद्योगिक आस्थानों को सिडकुल के मानदंडों और विनियमों के अनुसार विकसित और अधिसूचित किया जायेगा।
- xvi. आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेज आवश्यकताओं पर विस्तृत दिशानिर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।
- xvii. सीडा को नीति को लागू करने और लाभार्थियों की प्रगति का समर्थन/निगरानी करने का अधिकार दिया जा रहा है।

6- निजी औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए वित्तीय प्रोत्साहन एवं संस्थागत सुविधायें :

उत्तराखण्ड शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग वित्तीय प्रोत्साहनों के साथ-साथ संस्थागत सहायता के लिए नोडल एजेंसी और एक सूत्रधार के रूप में कार्य करेगा औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन/अनुदान सहायता व्यावसायिक गतिविधियों की स्थापना एवं प्रारम्भ होने के बाद देय होगी। इस नीति/योजना के तहत स्थापित किए जाने वाले निजी औद्योगिक आस्थान/क्षेत्रों को भारत सरकार और राज्य द्वारा संचालित योजना में से केवल एक ही स्रोत से एक ही बार में एक ही घटक पर लाभ प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी।

- i. निजी औद्योगिक पार्क/आस्थान की स्थापना के लिए विभिन्न विभागों से वांछित सभी आवश्यक अनुमोदन/अनुमति/अनुज्ञा/सहमति प्रमोटर द्वारा स्वयं प्राप्त की जाएगी।
- ii. स्व-टिकाऊ मरम्मत और रखरखाव: पार्क में बाहरी और आंतरिक बुनियादी ढांचे की मरम्मत और रखरखाव के लिए संपत्ति के प्रमोटर द्वारा संचालन और रखरखाव के लिए पूंजीगत व्यय कोष बनाया जाएगा। भूखण्डों की बिक्री से प्रमोटर द्वारा एकत्र की गई राशि का 2 प्रतिशत इस फंड में फिक्स्ड डिपोजिट के रूप में जमा किया जाएगा। इस फिक्स्ड डिपोजिट के

प्रबंधन और संचालन के लिए एक सोसाइटी/समिति (सोसाइटी एक्ट 1928 के तहत) का गठन किया जाएगा। समिति में प्रमोटर और आस्थान में स्थापित इकाइयों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

iii. सिडकुल औद्योगिक अवसंरचना विकास कोष (SHDF):

a) भूमि के समतलीकरण, लिंक रोड, ड्रेनेज, सीवररेज आदि सुविधाओं के विकास तथा आस्थान के लिए बाहरी बुनियादी ढांचे की स्थापना हेतु रु. 100 करोड़ का प्रारंभिक कोष बनाया जाएगा। इस कोष में से, औद्योगिक आस्थानों के लिए सृजित अवल परिसंपत्तियों पर किए गए कुल पूंजी निवेश के सापेक्ष बाह्य ढांचागत सुविधाओं के विकास पर प्रति पार्क विकास लागत का केवल 2 प्रतिशत सहायता स्वीकृत की जाएगी। यह स्वीकृत राशि सिडकुल द्वारा उत्तराखण्ड सरकार के संबंधित विभागों को स्वीकृत बाहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए हस्तांतरित की जाएगी।

b) SHDF के तहत रु. 100 करोड़ के इस कोष का प्रबंधन सिडकुल द्वारा किया जाएगा।

बाहरी बुनियादी ढांचे के सभी प्रस्तावों को एकल खिड़की व्यवस्था के माध्यम से परिचालित कर राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, राज्य प्राधिकृत समिति विकासकर्ता से बाहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कुछ राशि का योगदान करने के लिए कह सकती है।

iv. बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत उपादान:

a) सरकार किसी भी निजी क्षेत्र के निवेशक, व्यवसायिक संस्था आदि द्वारा प्रवर्तित प्रत्येक औद्योगिक पार्कों/आस्थानों की अवसंरचना लागत के बिक्री योग्य क्षेत्र (रु. 250 प्रति वर्ग मीटर/अनुपात आधार पर) पर 10 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से पूंजीगत अनुदान प्रदान करेगी।

b) सरकार निम्नानुसार स्वीकृत पूंजीगत उपादान धनराशि जारी करेगी:

1) परियोजना की 'सैद्धांतिक स्वीकृति' जारी होने के बाद परियोजना हेतु प्रस्तावित भूमि के अधिग्रहण, स्थल विकास, ले-आउट की स्वीकृति आदि का कार्य पूर्ण होने पर इस कार्य पर किये गये पूंजीगत व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर कुल अनुदान के विरुद्ध अनुदान राशि का 10 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

2) स्वीकृत अनुदान की 25 प्रतिशत राशि आंतरिक सड़कों एवं नालियों के निर्माण, विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था, विद्युत उपकेंद्र की स्थापना आदि जैसी आधारभूत संरचना सुविधाओं के विकास पूर्ण होने पर जारी की जायेगी।

3) स्वीकृत अनुदान का 40 प्रतिशत राशि कुल बिक्री योग्य भूखण्डों में से 60 प्रतिशत भूखण्डों की बिक्री के बाद देय होगी।

4) स्वीकृत अनुदान का अवशेष 25 प्रतिशत राशि औद्योगिक आस्थानों के पूर्ण संचालन तथा भूखण्ड क्रय करने वाली कुल इकाइयों में से 50 प्रतिशत उद्योगों की स्थापना पर देय होगी।

5) स्वीकृत वित्तीय प्रोत्साहनों का संचितरण:

- a) एक एस्करो खाते के माध्यम से, यदि निवेशक इस नीति के तहत खण्ड 5(ix) के अनुसार सिडकुल ब्रांड का उपयोग करता है, जहां सिडकुल त्रि-पक्षीय समझौते के तहत तीन पक्षों में से एक है।
- b) औद्योगिक विकास विभाग द्वारा सीधे, यदि निवेशक इस नीति के तहत खण्ड 5(ix) के अनुसार सिडकुल ब्रांड का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं है।

(सक्षम प्राधिकारी/प्राधिकृत समिति द्वारा विधिवत अनुमोदित होने पर।)

- v. सीआईडीपीडी की स्थापना पर उपादान: संयुक्त उत्प्रेषण शुद्धिकरण संयंत्र (CEEP) की स्थापना हेतु संयंत्र पर किये गये अचल पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत, अधिकतम रु. 1 करोड़ तक का पूंजीगत उपादान।
- vi. इस नीति के तहत निजी क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों/पार्कों में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाइयों को एमएसएमई नीति-2018 (यथासंशोधित-2018, 2018, 2019, 2020 व 2021)/बृहत औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018/मेगा औद्योगिक एवं निवेश नीति-2021 में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ पात्रता के आधार पर अनुमन्य होगा, परन्तु इन औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों में भूमि क्रय करने वाली इकाइयों को मेगा औद्योगिक एवं निवेश नीति-2021 में प्रदान की गई भूमि के मूल्य में कोई रियायत/छूट नहीं दी जाएगी।

नीति के क्रियान्वयन के लिए मानक प्रचलनात्मक प्रक्रिया एवं दिशानिर्देश पृथक से प्रशासनिक विभाग द्वारा बाद में पृथक से जारी किये जायेंगे।

7- नीति का कार्यान्वयन:

- i. यह नीति इसकी अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होगी और पांच वर्ष तक प्रवृत्त रहेगी।
- ii. राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगा और इस नीति को आवश्यक संशोधन अथवा परिवर्धन के साथ संशोधित किया जा सकेगा, जैसा कि आवश्यक हो, समय-समय पर इसे अधिसूचित किया जा सकेगा।
- iii. नीति के क्रियान्वयन और नीति से लाभान्वितों की प्रगति को अनुश्रवण/निगरानी करने के लिए सीडा अधिकृत रहेगी।
- iv. इस नीति में किसी भी संशोधन के मामले में, यदि राज्य सरकार द्वारा पहले से ही किसी इकाई को प्रोत्साहन का कोई पैकेज दिया गया है, तो उसे वापस नहीं लिया जाएगा और इकाई लाभ की हकदार बनी रहेगी।
- v. नीति में प्रदत्त लाभ सभी अनुमन्य होंगे, जब इकाई की बिलिंग का पता पूंजीगत व्यय के साथ-साथ परिचालन उद्देश्य के लिए उत्तराखण्ड में स्थित हो।

- vi. राज्य की किसी भी नीति में लाभ प्राप्त करने वाली पात्र इकाई इस नीति के प्रोत्साहन का लाभ उठाने की हकदार नहीं होगी जब तक कि अन्यथा अधिसूचित न हो।
- vii. यह विशेष वित्तीय प्रोत्साहन भारत सरकार की किसी भी योजना से इकाइयों द्वारा प्राप्त किए जा रहे किसी भी प्रोत्साहन के अतिरिक्त होगी।

Notification No: 373 /VII-3-23/04(03)-MSME/2020 Dated: 22 February, 2023

Annexure

Policy for the Establishment of Industrial Estates/Areas in the Private Sector-2023

1- Background and Vision:

The Government of Uttarakhand is actively promoting the use of private land for industrial use through the development of integrated Industrial Parks in the State. Industrial parks are the centre of economic activity and contribute heavily towards value addition and employment creation in the State.

The state is facing scarcity of government owned land during the time of accelerated industrial growth, to create the employment opportunities in Uttarakhand, more involvement of private parties is required. This policy encourages the participation of the private sector by establishing special industrial zones, export zones, theme parks, biotechnology parks, integrated industrial estates/ areas in the state of Uttarakhand, the Government of Uttarakhand promulgated a policy for the establishment of private industrial estates/ areas (vide G.O. no. 11/I.D./07-Industry/2004 dated 27, January 2004 and the G.O. No. 940/I.D./07-Industry/2004-05 dated 09 November 2004). Also, to promote industrial development in the hilly regions of the state, under Special Integrated Industrial Promotion Policy-2008, notified vide notification no. 488/VII-11/08/08 by Govt. of Uttarakhand, the minimum limit of land for the establishment of private industrial estates in hilly areas is 2 Acres and for the development of infrastructure facilities in industrial estates such as electricity, water, road, connecting roads & drainage system, 50 percent of the total expenditure on these facilities, maximum up to Rs. 50 lakh will be reimbursed as a grant to the promoters of the industrial estate.

A total of 49 private industrial estates have been notified in the state comprising 3113.30 acres of land. In addition to this, the State Government has also been notified 446.46 acres of land as Special Industrial Areas for 26 mega projects with an investment of more than Rs. 50 crores.

In the policy promulgated in the year 2004, no financial incentive was given on infrastructure facilities in private sector industrial estates/areas. In the Special Integrated Industrial Promotion Policy-2008 disseminated for the hilly area, provision was made to give financial incentives on the expenditure on the development of infrastructure facilities in the industrial estates to be set up in the private sector.

The Uttarakhand Policy for Establishment of Private Industrial Parks/Estates/Areas – 2022 is being proposed as follows:

2-

Objective:

- i. To attract investment in the state by promoting the establishment of industrial estates/sectors in the private sector.
- ii. To ensure the availability of industrial plots/land for setting up industries.
- iii. To encourage private sector participation for the development of industrial areas.
- iv. Establishment of mini/major industrial estates and area specific parks in the state.
- v. To ensure balanced and planned industrial development by developing industrial infrastructure,

3-

Definition:

- i. 'Industrial Estate/Area' means the place/area which is declared by the State Government to be such estate/area through notification.
- ii. "Facility" includes road, water supply, street lighting, electricity supply, sewerage system, drainage, collection, treatment and disposal of industrial waste & garbage and such other community work, service or facility as may be prescribed by the State Government by notification, specify as a convenience for the implementation of this policy.
- iii. "Occupier" means a person (including a firm or a body of persons, whether incorporated or not) having the jurisdiction of any site or building within the industrial establishment/area and "Occupier" includes his successor and assignee.
- iv. "Transferee" means a person (including any firm or other body of persons, whether incorporated or not), to whom land or building is transferred in any manner under this Act and the transferee includes his successor and There is also an assignee.
- v. The words and expressions "building", "development", "construction of building" and "land" shall have the same meanings as defined in the Uttarakhand General Industrial Development Regulations, 2022 (UGIDCR-2022).
- vi. "Commencement of business activity" of the industrial estate means the date on which commercial marketing of the industrial plots has been commenced by the promoter after the installation of infrastructure facilities on a commercial scale, for which the originator has been authorized or approved.
- vii. "Establishment of industrial estate/area" means from the date of regulation of industrial estate/area approved in principle.
- viii. "Department" means the Department of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of Uttarakhand.
- ix. "Empowered Committee" or "SLEC" means the State Level Empowered Committee defined in The Uttarakhand Entreprises and Single Window Facilitation and Clearance Act, 2012 (Adhiniyam Sankhya 05 of 2013).
- x. "Plain area" means the areas falling under Category C and Category D as per the Uttarakhand Micro, Small and Medium Enterprises Policy 2015 (as amended- 2016, 2018, 2019, 2020 & 2021).

- xi. "Hill Area" means the areas/districts falling under Category-A, Category-B and Category-B+ classified as per the Uttarakhand Micro, Small and Medium Enterprises Policy-2015 (as amended 2016, 2018, 2019, 2020 & 2021), as defined under Office Memorandum number 184/VII-2-15/146-MSME/2013 dated 31 Jan 2016 and Office Memorandum number 544/VII-2-16/146-MSME/2013 dated 22 Mar, 2016
- xii. "Industrial Park/Estate" means an industrial estate developed for the establishment of industrial units for the construction of a good or service and having developed plots, internal roads, water distribution facilities, sewage collection and treatment, there should be basic facilities like power distribution, communication facility.
- xiii. "Industrial Unit" means an industrial undertaking or a service sector unit other than a unit run by the Government departmentally, which is a registered business enterprise under the Goods and Services Tax.
- xiv. "Mini Industrial Estate" means such industrial estate/area developed on minimum 2 acres or more land in the hilly areas of the state.
- xv. "Policy" means Policy-2022 for Establishment of Private Industrial Estates/Area.
- xvi. "Person" as per defined under The Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016
- xvii. "Promoter" as per defined under The Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016
- xviii. "Sector Specific Industrial Park" means a specific park identified for sector specific industries, namely:
 - a) Garment Fibre and Textile Park
 - b) IT Park/Software Technology Park
 - c) Gem and Jewellery Park
 - d) Food park
 - e) Biotech
 - f) Ayush and Wellness Park
 - g) Automobile Ancillary Industry Park
 - h) Aroma Park
 - i) Aerospace & Defence Park
 - j) Knowledge Park
 - k) Film City / Sector
 - l) Service Sector Park (Aerocity, Medicity, Educity, and parks to establish units which undertake business activities such as film production, entertainment, education, medical facilities etc.)
 - m) Any other specific sector park

- xvix. "Escrow Agent" as defined under Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011.

4- Policy Validity Period:

- i. This policy will come into force from the date of issue of the notification and will be effective for the next five years.
- ii. The State Government can amend this policy at any time on the approval of the Hon'ble Cabinet as and when needed.
- iii. The right to provide any kind of relaxation in the provisions of this policy will be vested in the Government.

5- Eligibility & Procedure:

- i. Private industrial estate/area can be set up by an individual promoter/ developer/ partnership firm/ LLP/ company or any entity registered under the Companies Act/ Society Act/ Limited Liability Partnership Act, Joint Ventures, entities established under Public Private Partnership mode, Land Agregators (with consent in writing from all the concerned land owners) .
- ii. The promoter will have to arrange the land himself for the establishment of the industrial estate/area. To purchase land for industrial purpose under section-154 (4)(3)(a)(v) of UZALR Act for the necessary approvals/permissions/no-objections from various departments for the establishment of the Estate and for the acquisition of land. Cooperation will be provided by the department in obtaining permission.
- iii. Under this policy, assistance will be provided to the following participants
 - a) Manufacturing/ Infrastructure companies
 - b) Anchor Investors
 - c) Industry Associations having large numbers of regional and national memberships
 - d) Group of Enterprises
 - e) Joint Ventures, entities established under PPP mode
 - f) Eligible unit/entity/company referred to in clause 5(i) of this policy.
- iv. **Project Land:**
 - a) Investor to procure land from private parties from own sources
 - b) In case investor desires to obtain land from SIIDCUL; the investor shall have to make a proposal for land requirement to the SIIDCUL. Whereby the SIIDCUL board shall take a decision with terms and conditions (i.e. land leasing tenure, sub-leasing etc.) on the proposal.
 - c) In case of Land Agregators SIIDCUL shall enter into the agreement with promoter to act as a regulator for ensuring the financial obligations paid-off before withdrawing any profit by the promoter.

- v. For the establishment of a private industrial estate, it is necessary to have a minimum of 30 acres in the plain area and a minimum of 2 acres or more land in the hilly area.
- vi. Development/ establishment/ regulation of IT Park/ Biotechnology Park in the private sector must be as per prevailing building bye-laws of SIDA; with a minimum builtup area of 18,000 sqmtr.
- vii. The proposed land should be duly in full possession of the promoter and free from any encroachment.
- viii. These private industrial areas would follow SIDA norms for development.
- ix.
 - a) Promoter may utilize brand image of SIIDCUL by taking consent from Board of Directors of SIIDCUL with agreed terms and conditions. SIIDCUL may charge a management fee for ensuring, implementing, and regulating the park development as per norms.
 - b) The allotment, transfer, and division of the plots in saleable area of the industrial park shall be transacted through a tri-party agreement between promoter, SIIDCUL and Escrow Agent.
- x. For the development of industrial estates/area, necessary Approvals/ Acceptance/ No-objection will be required to obtain from various departments, the promoter/ organization/ company will be obtained himself, in which the Department of Micro, Small and Medium Enterprises will provide the requisite support in obtaining the desired approval/ permission/ approval/ no-objection under the provisions of the Single Window Clearance System.
- xi. General Industrial Development Control Regulations-2022 / Unified Building by-laws for the development of industrial estates/areas will follow the prescribed land use standards for building construction and land subdivision and industrial estates, for which Uttarakhand State Industrial Development Authority, regulatory will act as authority.
- xii. In such industrial establishments, the responsibility of maintaining the infrastructure facilities, maintenance of drains, internal roads, lighting and other civic amenities will be the responsibility of the promoter organization / company/ owner of the concerned estate/area.
- xiii. In the private industrial estate, the rates of industrial plots will be determined and marketed by the promoter / board of directors of the estate itself. The state government will have no role in this.
- xiv. An agreement will be signed with the allottees by the promoters of the Estate, in which all the primary infrastructure facilities to be provided in the Estate, the rates of the plot, the amount to be charged annually for maintenance and the conditions must be clearly mentioned.
- xv.
 - (1) The process of In-Principle approval/regulation for the establishment of a private industrial estate/area will be of two stages:
 - a) In the first phase, only In-Principle approval will be given on the application of the entrepreneur/ institution/ company desirous of setting up the Industrial Estate.

- b) In the second phase on production of completion certificate according to the layout plan approved by SIDA on the land acquired for the estate/ area and to ensure that the conditions and restrictions are fully complied within the In-Principle approval letter issued for the establishment of the Estate. A formal notification will be issued in this regard.

(2) All PPP/Joint Venture industrial estates to be developed and notified as per SHDCUL norms and regulations.

- xvi. Detailed guidelines on application procedure, document requirements shall be published separately.
- xvii. SIDA is being empowered to implement the policy and support/ monitor the progress of beneficiaries.

6- Financial incentives and institutional facilities for the development of private industrial parks:

The State Micro, Small and Medium Enterprises Department will act as nodal agency and a facilitator for institutional support along with the financial incentives. The financial incentive/ grant assistance to the units of industrial area/ park will be payable after the establishment and starting of business activities. Private industrial estates/ areas to be established under this policy/ scheme will be allowed to avail the benefits on the same component at once from one source only, either from the scheme run by the Government of India and the State.

- i. All the necessary approvals/ permissions/ clearances/ consents required from various departments for establishing the private industrial park/ estates shall be obtained by the promoter.
- ii. **Self-sustainable Repair & Maintenance:** Capital expenditure fund for O&M will be created by the promoter of the estate for the repair and maintenance of the external and internal infrastructure in the park. 2% of the amount collected by the promoter from the sale of land parcels will be deposited in this fund as FD. A society/ committee (under the Societies Act 1928) will be constituted to manage and operate this FD. The committee will consist of promoters and representatives of the units established in the estate.
- iii. **SHDCUL Industrial Infrastructure Development Fund (SIIDF):**
 - a) Initial corpus of INR 100 crore will be made available for setting up of external infrastructure for the estates such as land filling, link roads drainage, sewerage etc. Out of this fund, only 2% of development cost per Park shall be sanctioned on the development of external infrastructural facilities relative to the total capital investment made on the fixed assets created for the industrial Estates; this sanctioned amount shall be transferred by SHDCUL to the respective departments of Government of Uttarakhand for developing the approved external infrastructure.
 - b) This corpus of INR 100 crore under the SIIDF shall be managed by SHDCUL.

All proposals of external infrastructure shall be applied through Single Window system and shall be approved by SLEC, whereby the empowered committee may ask developer to contribute certain amount for development of external infrastructure.

iv. Capital Subsidy on Infrastructure:

- a) Government will provide capital grant at the rate of INR 10 lakh per acre on saleable area (INR 250 per square meter/ Pro-rata Basis) of infrastructure cost of each industrial parks/ estates promoted by any private sector investor, business entity etc.
 - b) The government will release the approved capital subsidy amount as follows:
 - 1) After the issuance of 'In-Principle Approval' of the project, the work of acquisition of proposed land for the project, site development, approval of the layout etc. is completed and on production of the utilization certificate of the capital expenditure incurred on this work, 10 percent of the subsidy amount shall be payable against the total subsidy.
 - 2) 25 percent of the sanctioned grant shall be released on the development of basic infrastructure facilities, such as construction of internal roads and drains, arrangement for power supply, establishment of electric sub-station etc.
 - 3) The 40 percent of the sanctioned grant shall be payable after the sale of 60 percent of the saleable plots.
 - 4) The remaining 25 percent of the sanctioned subsidy shall be payable on the complete operation of the industrial estates and establishment of 50 percent industries out of total number of units who purchased land parcels.
 - 5) All sanctioned financial incentives shall be disbursed:
 - a) Through an escrow account, if the investor uses SIIDCUL brand as per the clause 5(ix) under this policy, where SIDCUL is one of the three parties under tri-party agreement.
 - b) By the Department of Industrial Development directly, if the investor is not willing to use SIIDCUL brand, as per the clause 5(ix) under this policy.
- on duly approved by the Competent Authority/empowered Committee.

- v. Grant on setting up of CETP:** 40 percent Capital Subsidy, maximum up to Rs. 1 Crore of the fixed capital investment made on the plant for setting up a common effluent treatment plant.

- vi. Under this policy, industrial units to be set up in industrial estates/areas/parks set up in the private sector are eligible for the benefit of financial incentives provided in MSME Policy-2015 (as amended- 2016, 2018, 2019, 2020 & 2021) / Large Industrial Investment and Employment Promotion Policy-2018 / Mega Industrial and Investment Policy-2021. However, The units purchasing land in these industrial estates/areas will not be given any concession/rebate in the value of land provided in the Mega Industrial and Investment Policy-2021.

Standard, operational procedure and guidelines for the implementation of the policy will be issued separately by the administrative department later.

7. Policy Implementation:

- i. This policy will come into effect on the date of its notification and will remain in force for five years.
- ii. SLEC will review the implementation of the policy and this policy may be modified with necessary amendments or supersession as may be required and notified from time to time.
- iii. SIDA is being empowered to implement the policy and support monitor the progress of beneficiaries.
- iv. In case of any amendment in this policy, if any package of incentives is already committed by the State government to any unit, it shall not be withdrawn and the unit shall continue to remain entitled to the benefits.
- v. Benefits will only be applicable in case the unit's billing address is located in Uttarakhand for capital expenditure as well as for operational purposes.
- vi. The eligible unit that has availed any benefits in any of the State's policies shall not be entitled to avail incentives of this policy unless otherwise notified.
- vii. This special financial assistance shall be over and above any incentives being availed by the units from any Government of India Scheme.

अधिसूचना

22 फरवरी, 2023 ई०

संख्या 374/VII-3-23/04(01)/एम०एस०एम०ई०/2022-

उत्तराखण्ड प्रतिबन्धित सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री के वैकल्पिक उत्पादों के विनिर्माण हेतु नीति-2023

प्रस्तावना: उत्तराखण्ड शासन, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग की अधिसूचना संख्या 84/XXXVIII-1-20-13(11)/2001 दिनांक 16.02.2021 द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक, जिसमें किसी भी आकार, मोटाई माप व रंग के प्लास्टिक कैंरी बैग (हैण्डल के साथ अथवा बिना हैण्डल के) और नॉन-वोवन पॉली प्रोपाईलिन बैग, थर्मोकोल (पॉलीस्टायरीन), पॉलीयुरेथेन, स्टायरोफोम और इसी तरह के बने एकल उपयोग के डिस्पोजेबल कटलरी या प्लास्टिक जैसे प्लेट ट्रे, कटोरे, कप, गिलास, घुमच, कांटा, स्ट्रॉ, चाकू, स्ट्रिपर आदि, चाहे वे किसी भी आकार व प्रकार के हों, के उत्पादन, क्रय विक्रय, आयात, भण्डारण, उपयोग व आपूर्ति सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में प्रतिबन्धित की गयी है,

इसके अतिरिक्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-साठका०नि 571(अ) दिनांक 12 अगस्त, 2021 के द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2022 से पॉलीस्टाइरीन और विस्तारित पॉलीस्टाइरीन वस्तुओं सहित प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बक्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की इंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की स्टिक, पॉलीस्टाइरीन (थर्मोकोल) की सजावटी सामग्री, प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसे कटलरी मिठाई के डिब्बों के इर्द-गिर्द लपटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैग, स्ट्रॉ आदि के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को भी प्रतिबन्धित किया गया है।

सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के उपयोग, भण्डारण, विनिर्माण, क्रय-विक्रय पर प्रतिबन्ध लगाये जाने से राज्य में इन उत्पादों के निर्माण में संलग्न इकाइयों में उत्पादन कार्य बन्द हो गया है और इन इकाइयों में सृजित रोजगार भी इससे प्रभावित हुआ है। इसको दृष्टिगत रखते हुए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रदूषण से निपटने और एकल उपयोग प्लास्टिक के उन्मूलन के क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देकर सिंगल यूज प्लास्टिक (एकल उपयोग प्लास्टिक) के विकल्प (Alternatives) के रूप में अनुबन्ध-1 में दिये गये उत्पादों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2016 (समय-समय पर यथासंशोधित) में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों के अतिरिक्त टॉप-अप सहायता के रूप में कुछ अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन दिये जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है।

अतः एकल उपयोग प्लास्टिक प्रतिबन्ध से प्रभावित इकाइयों को वैकल्पिक या गैर-प्रतिबंधित उत्पादों की नई इकाइयों की स्थापना अथवा मौजूदा इकाई के विविधीकरण (Diversification) को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तराखण्ड प्रतिबन्धित सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री के वैकल्पिक उत्पादों के विनिर्माण हेतु नीति-2023 प्रस्तावित की जा रही है।

उद्देश्य:

- प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पाद के निर्माण में लगे हुए उद्यमियों को प्रोत्साहित करना।
- बाजार में एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों के प्रचलन को समाप्त करना।
- हरित उत्पादों, बायोप्लास्टिक्स, बायो-डिग्रेडेबल प्लास्टिक्स/कम्पोस्टेबल प्लास्टिक्स, ऑक्सो-डिग्रेडेबल प्लास्टिक्स तथा कृषि अवशेष से बनी पैकेजिंग सामग्री/कैरी बैग आदि के उपयोग हेतु जागरूकता पैदा करना।
- 'प्लास्टिक मूल्य श्रृंखला' में मौजूदा इकाइयों के लिए प्रौद्योगिकी में बदलाव।
- प्लास्टिक उद्योग में कच्चे माल के उत्पादन से प्लास्टिक के निपटान तक चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना।
- वैकल्पिक प्लास्टिक के विकल्पों में नवाचार को बढ़ावा देकर अनुसंधान और अवसंरचना ढांचे की स्थापना।

नीति की वैधता अवधि:

यह नीति अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी तथा आगामी पांच वर्षों तक प्रभावी रहेगी।

पात्रता/अनिवार्य अपेक्षा:

- भारत सरकार/उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रतिबन्धित/प्रतिषेध सिंगल यूज प्लास्टिक विनिर्माणक, प्रतिबन्ध प्रभावित इकाइयां।

- सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के विनिर्माण के लिए इनपुट सामग्री/मध्यवर्ती सामग्री का निर्माण करने वाली इकाईयां।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत ईएम पार्ट-2/उद्योग आधार/उद्यम रजिस्ट्रेशन की अभिस्वीकृति प्राप्त की हो।
- माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत राज्य में पंजीकरण होना आवश्यक होगा।
- उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से उद्यम स्थापना/उत्पादन प्रारम्भ करने के लिए सहमति प्राप्त की हो।

प्रभावित अर्ह इकाईयों को वित्तीय प्रोत्साहन:

प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए वर्तमान में विनिर्माणक तथा सेवा क्षेत्र के चिन्हित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति, 2015 (समय-समय पर यथासंशोधित) नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों में से निम्न मदों में टॉप-अप के रूप में अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन दिये जाने का प्रस्ताव है:

सिंगल यूज प्लास्टिक विनिर्माणक वे इकाईयां, जो प्रतिबन्ध के कारण प्रभावित हुई हैं, को वैकल्पिक उत्पाद के निर्माण हेतु क्रय किये गये नये प्लांट व मशीनरी पर एमएसएमई नीति, 2015 में प्रदत्त पूंजी निवेश सहायता तथा ब्याज उपादान सहायता के साथ ही इन मदों में इस नीति में प्रदत्त टॉप-अप सहायता का लाभ अनुगम्य होगा।

1. निवेश प्रोत्साहन सहायता:— उद्यम के प्लांट व मशीनरी तथा कार्यशाला भवन में किये गये अचल पूंजी निवेश पर वर्गीकृत श्रेणियों के अनुसार एमएसएमई नीति में प्रदत्त निवेश प्रोत्साहन सहायता के अतिरिक्त टॉप-अप के रूप में अतिरिक्त प्रोत्साहन सहायता निम्नानुसार दी जायेगी।

| क्र. सं. | जनपद/क्षेत्र का वर्गीकरण | एमएसएमई नीति में प्रदत्त निवेश प्रोत्साहन सहायता की अधिकतम सीमा/मात्रा | सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन में लगी हुई प्रतिबन्धित इकाई को टॉप-अप के रूप में प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त प्रोत्साहन सहायता की मात्रा/सीमा |
|----------|--------------------------|--|--|
| 1. | श्रेणी- ए | 40 प्रतिशत (अधिकतम रु. 40 लाख) | 10 प्रतिशत (अधिकतम रु. 10 लाख) |
| 2. | श्रेणी- बी व बी-1 | 35 प्रतिशत (अधिकतम रु. 35 लाख) | 10 प्रतिशत (अधिकतम रु. 10 लाख) |
| 3. | श्रेणी- सी | 30 प्रतिशत (अधिकतम रु. 30 लाख) | 10 प्रतिशत (अधिकतम रु. 10 लाख) |
| 4. | श्रेणी- डी | 15 प्रतिशत (अधिकतम रु. 15 लाख) | 10 प्रतिशत (अधिकतम रु. 10 लाख) |

2. ब्याज उपादान:— उद्यम की स्थापना के लिए वित्तीय संस्था/बैंक से लिए गये सावधि ऋण पर देय ब्याज में एमएसएमई नीति में प्रदत्त ब्याज उपादान के अतिरिक्त टॉप-अप के रूप में निम्नानुसार अतिरिक्त ब्याज प्रोत्साहन सहायता दी जायेगी:

| क्र. सं. | श्रेणी | एमएसएमई नीति में प्रदत्त ब्याज प्रोत्साहन सहायता की अधिकतम मात्रा/सीमा | सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन में लगी हुई प्रतिबन्धित इकाई को टॉप-अप के रूप में प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त ब्याज प्रोत्साहन सहायता की मात्रा/सीमा |
|----------|--------|--|--|
|----------|--------|--|--|

| | | | |
|----|-------------------|---|--|
| 1. | श्रेणी- ए | 10 प्रतिशत अधिकतम रु. 08 लाख/प्रतिवर्ष/इकाई) | |
| 2. | श्रेणी-बी एवं बी+ | 08 प्रतिशत (अधिकतम रु. 06 लाख/प्रतिवर्ष/इकाई) | |
| 3. | श्रेणी- सी | 06 प्रतिशत (अधिकतम रु. 04 लाख/प्रतिवर्ष/इकाई) | एमएसएमई नीति, 2015 (समय-समय पर यथासंशोधित) में निर्धारित ब्याज उपादान दर की सीमा में, अधिकतम रु. 01 लाख/प्रतिवर्ष/प्रतिइकाई। |
| 4. | श्रेणी- डी | 05 प्रतिशत (अधिकतम रु. 03 लाख/प्रतिवर्ष/इकाई) | एमएसएमई नीति, 2015 (समय-समय पर यथासंशोधित) में निर्धारित ब्याज उपादान दर की सीमा में, अधिकतम रु. 02 लाख/प्रतिवर्ष/प्रतिइकाई। |

3. एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति : उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना दिनांक 16.02.2021 तथा भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 12 अगस्त, 2021 से प्रभावित इकाईयों को वैकल्पिक उत्पाद के विनिर्माण हेतु विद्यमान उद्यम के विविधीकरण अथवा नये उद्यम की स्थापना हेतु नये प्लांट व मशीनरी की खरीद पर देय जीएसटी में से राज्य सरकार को प्राप्त होने वाले कुल सकल एसजीएसटी (आईटीसी के समावोजन के उपरान्त) में से 20 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति सहायता दी जायेगी।

इन सुविधाओं का लाभ मात्र उन इकाईयों को उपलब्ध होगा, जिन्हें केन्द्र/राज्य सरकार के प्रतिबन्ध आदेश के कारण बन्द कर दिया गया है।

अनुबन्ध-1

नीति आयोग द्वारा "प्लास्टिक और उनके अनुप्रयोगों के लिए वैकल्पिक उत्पाद और प्रौद्योगिकी" में परिभाषित उद्यम

| ऐसे उत्पाद, जिनमें निम्नलिखित कच्चेमाज का उपयोग किया जाता है | पॉलीमर | सामान्य बायोमास स्रोत | सामान्य उपयोगों के उदाहरण |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| कपास | सेल्यूलोज | कपास का पौधा (गॉस्पियम एसपी.) | वस्त्र, अन्य कपड़े |
| हैम्प | सेल्यूलोज | हैम्प (कैनेबिस सैटीवा) | वस्त्र, अन्य कपड़े |
| फलैक्स/लिनैन | सेल्यूलोज | फलैक्स/लिनरीड (लिनम यूसीटेटीसिनम) | वस्त्र, अन्य कपड़े |
| जूट | सेल्यूलोज एवं लिग्निन | (कार्कोरस एसपी.) | बोर, कालीन, कपड़े, रस्सी, अन्य कपड़े |
| कॉपर फाइबर | सेल्यूलोज एवं लिग्निन | नारियल (बाहरी खोल) | चटाई ब्रश, बोरी, रस्सी, मछली पकड़ने के जाल |
| रैम | सेल्यूलोज | चाइना ग्रास (बोहमेरिया नीबिया) | वस्त्र, अन्य कपड़े, औद्योगिक सिलाई धागा |
| अबाका/मनीला हैम्प | सेल्यूलोज, लिग्निन एवं पेक्टिन | केला (मूसा टेक्सटीलिस, अखाद्य) | टी बैग, बैंकनोट, चटाई, रस्सी |
| पिना | सेल्यूलोज एवं लिग्निन | अनानास का पत्ता (अनानास कोमोसस) | वस्त्र, अन्य कपड़े |
| सिसल | | (अगावे सिसलाना) | कपड़ा, बैग, रस्सी, सुतली |

अन्य वैकल्पिक उत्पादः

1. जैवप्लास्टिक्स।
2. बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक।
3. कम्पोस्टेबल प्लास्टिक।
4. ऑक्सो-डिग्रेडेबल/ऑक्सीडिग्रेडेबल/ऑक्सी-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स,
5. कृषि अवशेषों, गत्ते और कागज से बनी कटलरी।
6. राम बांस से बनी वस्तुएं।
7. प्राकृतिक रेशों से बनी वस्तुएं।
8. कले की पत्तियों से बनी वस्तुएं।

आज्ञा से,

डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव।

In pursuance of the provision of the clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the translation of policy Notification No.374/VII-3-23/04(01)-MSME/2022 Dated February 22, 2023.

OFFICE MEMORANDUM

February 22, 2023

No.374/VII-3-23/04(01)-MSME/2022--

The Uttarakhand manufacturing of alternative products of banned single use plastic material policy, 2023.

Introduction:

Single use plastic, in which Production, purchase, sale, import, storage, use and supply of any kind and size of plastic carry bags (with or without handles) of any size, thickness measurement and colour and single-use disposable cutlery made of non-woven poly propylene bags, thermocol (polystyrene), polyurethane, styrofoam and similar product or plastic such as plate trays, bowls, cups, glasses, spoons, forks, straws, knives, stirrers, etc., have been banned in the entire state of Uttarakhand vide Government of Uttarakhand, Environment Protection and Climate Change Section's notification number 84/XXXVIII-1-20-13(11)/2001 dated 16.02.2021.

In addition, by notification no. G.S.R. 571(E) dated August 12, 2021, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, with the effect from July 01, 2022, has also been prohibited polystyrene and expanded polystyrene items including ear buds with plastic sticks, plastic India for balloons, plastic flags, Candy sticks, ice cream sticks, decorative materials of polystyrene (Thermocol), cutlery such as plates, cups, glasses, forks, spoons, knives, straws, trays, wrapping or packing films for sweet boxes, invitation cards and The manufacture, import, storage, distribution, sale and use of cigarette packets, plastic or PVC banners, strips, etc. of thickness less than 100 microns.

Due to the ban on the use, storage, manufacturing, purchase and sale of single use plastic products, the production work has stopped in the units involved in the manufacture of these products in the state and the employment generated in these units has also been affected. Keeping this in view, to deal with plastic waste pollution and to promote innovation and entrepreneurship

in the field of elimination of single use plastic and to encourage manufacturing of products given in Annexure-1 as alternatives to single use plastic. There is a need to provide some additional financial incentives in the form of top-up assistance in addition to the financial incentives provided in the Micro, Small and Medium Enterprises Policy-2015 (as amended from time to time).

Therefore, to encourage units affected by single use plastic ban to set up new units of alternative or non-restricted products or to encourage diversification of existing units, The Uttarakhand manufacturing alternative products of banned single use plastic material, policy-2023 is being proposed.

Objective:

- To encourage entrepreneurs engaged in the manufacture of alternative products to plastic.
- To eliminate the prevalence of single-use plastic products in the market.
- To create awareness for the use of green products, bioplastics, bio-degradable plastics/compostable plastics, oxo-degradable plastics and packaging materials/carry bags made from Agri-residues etc.
- Technology shift for existing units in the 'Plastics Value Chain'.
- Promotion of circular economy in the plastics industry from raw material production to disposal of plastics.
- Establishment of research and analysis infrastructure by promoting innovation in single use plastic alternatives.

Policy validity period:

This policy will come into force from the date of issue of the notification and will be effective for the next five years.

Eligibility / Mandatory Requirement:

- Units affected by ban on manufacturing of single use plastic imposed by Government of India/Government of Uttarakhand, ban affected units.
- Units manufacturing input material/intermediate material for manufacturing single use plastic products.
- Under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, EM Part-2 / Udyog Aadhaar / Acknowledgment of Enterprise Registration has been obtained.
- Under the Goods and Services Tax Act, 2017, it will be necessary to register in the state.
- Consent has been obtained from the Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board for setting up the enterprise/starting production.

Financial incentives to affected eligible units:

Under State's Micro, Small and Medium enterprises Policy, 2015 (as amended time to time), to encourage the establishment of micro, small and medium enterprises in the state and to encourage the establishment of currently identified micro, small and medium enterprises in the manufacturing and service sector, it is proposed to give additional financial incentives in the form of top-up apart from the financial incentives provided in the policy to the following items:

Units of single-use plastic manufacturing, which have been affected due to the ban, along with the capital investment assistance and interest subvention assistance provided in the MSME Policy, 2015 on the purchase of new plant and machinery for the manufacture of alternative products, these items will also be included in this policy. The benefit of top-up assistance will be provided as under.

1. **Investment Promotion Assistance:** - According to classified category on immovable capital investment done in plant and machinery of Industries and workshop building, in addition to the investment promotion assistance provided in the MSME policy, additional incentive assistance in Form of additional top up shall be given as follows:

| S.No. | Classification of District/Area | Maximum limit/quantity of investment promotion assistance provided in MSME policy | Quantum/extent of additional incentive assistance to be provided as top-up to the banned unit engaged in the production of single use plastic |
|-------|---------------------------------|---|---|
| 1. | Category-A | 40% (Max Rs. 40 Lakh) | 10% (Max Rs. 10 Lakh) |
| 2. | Category-B & B+ | 35% (Max Rs. 35 Lakh) | 10% (Max Rs. 10 Lakh) |
| 3. | Category-C | 30% (Max Rs. 30 Lakh) | 10% (Max Rs. 10 Lakh) |
| 4. | Category-D | 15% (Max Rs. 15 Lakh) | 10% (Max Rs. 10 Lakh) |

2. **Interest Subsidy:** - In addition to the interest subvention provided in the MSME policy, additional interest incentive assistance will be given as a top-up in the interest payable on the term loan taken from the financial institution/bank for the establishment of the enterprise as follows:

| S.No. | Category | Maximum amount / limit of interest incentive assistance provided in MSME policy | Quantum/extent of additional interest incentive assistance to be provided as top-up to the banned unit engaged in the production of single use plastic |
|-------|-----------------|---|--|
| 1. | Category-A | 10% (maximum Rs. 08 lakh/annum/unit) | - |
| 2. | Category-B & B+ | 08 % maximum Rs. 06 lakh/annum/unit) | - |
| 3. | Category-C | 06 % (maximum Rs. 04 lakh/annum/unit) | Within the limit of interest subvention rate prescribed in MSME Policy, 2015 (as amended time to time), a maximum of Rs. 01 lakh/annum/per unit. |
| 4. | Category-D | 05 % (maximum Rs. 03 lakh/annum/unit) | Within the limit of interest subvention rate prescribed in MSME Policy, 2015 (as amended time to time), a maximum of Rs. 02 lakh/annum/per unit. |

3. **Reimbursement of SGST:** The units affected by the Government of Uttarakhand Notification dated 16.02.2021 and Government of India notification dated August 12, 2021, shall be given reimbursement assistance of 20 percent of the total gross SGST (After adjustment of ITC) to be received by the state government out of the GST payable on the purchase of new plant and machinery for the diversification of the existing enterprise or for the establishment of a new enterprise for the manufacture of alternative products.

The benefit of these facilities shall be available only to those units, which have been closed due to the ban order of the Central / State Government.

Annexure-1

Enterprises as defined by NITI Aayog in "Alternative Products and Technologies for Plastics and their Applications"

| Products in which the following raw materials are used | Polymers | Common Biomass source | Examples of common usage |
|--|----------------------------|------------------------------------|---|
| Cotton | Cellulose | Cotton plant (Gossypium sp.) | Clothing, other fabrics |
| Hemp | Cellulose | Hemp (Cannabis sativa) | Clothing, other fabrics |
| Flax/Linen | Cellulose | Flax/linseed (Linum usitatissimum) | Clothing, other fabrics |
| Jute | Cellulose & lignin | (Corchorus sp.) | Sacks, carpets, clothing, rope, other fabrics |
| Coir fibre | Cellulose & lignin | Coconut (outer shell) | Mats, brushes, sacking, rope, fishing nets |
| Ramie | Cellulose | China grass (Boehmeria nivea) | Clothing, other fabrics, industrial sewing thread |
| Abaca/Manila hemp | Cellulose, lignin & pectin | Banana (Musa textilis, inedible) | Tea bags, banknotes, matting, rope |
| Pina | Cellulose & lignin | Pineapple leaf (Ananas comosus) | Clothing, other fabrics |
| Sisal | | (Agave sisilana) | Textiles, bags, rope, twine |

Other Optional Products:

1. Bio-plastics.
2. Bio-degradable Plastic.
3. Compostable Plastics.
4. Oxo-degradable/Oxy-degradable/Oxy-biodegradable plastics.
5. Cutlery made from agricultural residues, cardboard and paper.
6. Items made of Ram Bamboo.
7. Articles made from natural fibers.
8. Articles made from banana leaves.

By Order

DR. PANKAJ KUMAR PANDEY,

Secretary

गृह अनुभाग 1**पदोन्नति आदेश**

07 फरवरी, 2023 ई०

संख्या I/97138/2023—श्री पूरन सिंह रावत, गिरीक्षक (एम)/गोपनीय सहायक, पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को शिक्ति के सापेक्ष पुलिस उपधीक्षक(एम)/पी.एस. (पे मैट्रिक्स में लेवल-10) के पद पर दिनांक 01.02.2023 से पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्री पूरन सिंह रावत को उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की विहित परीक्षा पर रखा जाता है।

आज्ञा से,
अतार सिंह,
अपर सचिव।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग—1**अधिसूचना****त्यागपत्र स्वीकृति**

07 फरवरी, 2023 ई०

संख्या 96818/XXVIII-2023-ई०-32796/2022—एतद्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या-24/रा०मा०/००/2018/23343, दिनांक 18.09.2022 के क्रम में उत्तराखण्ड सरकारी सेवक त्यागपत्र नियमावली, 2003 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत डा० निधि राणा, नियमित चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मोटाहल्दू नैनीताल का त्याग-पत्र दिनांक 01.08.2021 से स्वीकृत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
अमनदीप कौर,
अपर सचिव।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 11 मार्च, 2023 ई0 (फाल्गुन 20, 1944 शक सम्वत्)

भाग 1—क

नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

February 20, 2023

No. 35/XIV-a/38/Admin.A/2012--Ms Shachi Sharma Civil Judge (Sr Div) Vikasnagar, District Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 59 days w.e.f 07.11.2022 to 04.01.2023

NOTIFICATION

February 20, 2023

No. 36/XIV-45/Admin.A/2008--Shri. Malik Mazhar Sultan the then District & Sessions Judge Almora presently posted as Chairman, Commercial Tax Tribunal, Uttarakhand, Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 15 days w.e.f. 28.11.2022 to 12.12.2022.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION*February 21, 2023*

No. 37/UHC/Admin.A/2023--Pursuant to the Order dated 20.02.2023 of Hon'ble High Court of Uttarakhand passed in WPSB No. 65 of 2023 titled as Rajeev Kumar Vs. State of Uttarakhand; Shri Rajeev Kumar, Chairman, Permanent Lok Adalat Dehradun stands relieved from the charge of Chairman, Permanent Lok Adalat, Dehradun forthwith, subject to outcome of the Writ Petition (WPSB) No. 65 of 2023.

By Order of the Court,

Sd/-

ANUJ KUMAR SANGAL,

Registrar (Vigilance)

For Registrar General.

NOTIFICATION*February 22, 2023*

No. 39/XIV-a-44/Admin.A/2020--Ms. Avantika Singh Chaudhary, 3rd Additional Civil Judge, (Jr. Div.), Dehradun, is hereby sanctioned medical leave for 14 days w.e.f. 02.01.2023 to 15.01.2023.

By Order of Hon'ble the Vacation Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION*February 22, 2023*

No. 39/XIV/57/Admin.A/2003--Shri Ajay Chaudhary, 1st Additional District & Sessions Judge, Nainital is hereby sanctioned earned leave for 15 days w.e.f. 01.12.2022 to 15.12.2022.

NOTIFICATION*February 22, 2023*

No. 40/XIV/a-39/Admin.A/2017--Ms. Shalini Dadar, Civil Judge (Jr. Div.), Lansdowne, District Pauri Garhwal is hereby sanctioned earned leave of 24.12.2022 (single day) with permission to suffix 25.12.2022 to 01.01.2023 as winter holidays and New Years' holiday for the purpose of L.T.C.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

February 22, 2023

No. 41/XIV/a-35/Admin.A/2018--Ms. Karishma Dangwal, 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Kashipur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned medical leave for 11 days w.e.f. 12.01.2023 to 22.01.2023.

NOTIFICATION

February 22, 2023

No. 42/XIV-a-26/Admin.A/2011--Ms. Akata Mishra, 1st Additional Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun, is hereby sanctioned medical leave for 07 days w.e.f. 07.01.2023 to 13.01.2023.

By Order of Hon'ble the Vacation Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,

टनकपुर (चम्पावत)

आदेश

26 नवम्बर, 2022 ई०

पत्रांक:-2876/पंजीयन निरस्त/2022-23-वाहन संख्या UK035833 (HGV) मॉडल 2007 चैचिस 97VFJ75767P इंजन न० RZH095706 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्रीमती दीपा नेगी पत्नी श्री राजन सिंह निवासी-मकान संख्या 87 ग्राम-द्यूरी, पोस्ट-चल्थी, चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 21/11/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (सप्तसाखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का चैसिस निरस्त कर कार्यालय में जमा करा दिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह को बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 85(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 26.11.2022 को वाहन संख्या UK035833 (HGV) मॉडल 2007 चैचिस 97VFJ75767P इंजन न० RZH095706 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

28 नवम्बर, 2022 ई०

पत्रांक:-2877/पंजीयन निरस्त/2022-23-वाहन संख्या UP290841 (HGV) मॉडल 2000 चैचिस BS6618SVF इंजन न० 88VPJS0147P इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री जगदीश खर्कवाल पुत्र श्री घनश्याम खर्कवाल निवासी-वार्ड नम्बर 15 सैलानीगोट टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 17/11/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन नियम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का चेसिस निरस्त कर कार्यालय में जमा करा दिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 28.11.2022 को वाहन संख्या UP290841 (HGV) मॉडल 2000 चैचिस BS6618SVF इंजन न० 88VPJS0147P को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

28 नवम्बर, 2022 ई०

पत्रांक:-2878/पंजीयन निरस्त/2022-23-वाहन संख्या UTF6643 (HGV) मॉडल 1979 चैचिस VPJ546NE इंजन न० 101421122 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री मोहन चन्द्र गड़कोटी पुत्र श्री कंदार दत्त गड़कोटी निवासी-स्टेशन रोड टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 23/11/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन नियम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का चेसिस निरस्त कर कार्यालय में जमा करा दिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 28.11.2022 को वाहन संख्या UTF6643 (HGV) मॉडल 1979 चैचिस VPJ546NE इंजन न० 101421122 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

28 नवम्बर, 2022 ई०

पत्रांक:-2879/पंजीयन निरस्त/2022-23-वाहन संख्या UA034683 (HGV) मॉडल 2008 चैचिस 92VFJ64202P इंजन न० B72365SVF इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री विगल शर्मा पुत्र श्री प्रेमशंकर निवासी-मकान संख्या 219 मस्जिद वार्ड, टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 22/11/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का चैसिस निरस्त कर कार्यालय में जमा करा दिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 26.11.2022 को वाहन संख्या UA034683 (HGV) मॉडल 2008 चैचिस 92VFJ64202P इंजन न० B72365SVF को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

सुरेन्द्र कुमार,

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
टनकपुर (चम्पावत)।